



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012021-224206
CG-DL-E-05012021-224206

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]
No. 3]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2021/पौष 15, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2021/PAUSHA 15, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली 5 जनवरी, 2021

मामला सं. एडीडी-एसएसआर-07/2020

विषय – जापान और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “फथेलिक एनहाइड्राइड” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 7/11/2020-डी जी टी आर.—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ‘अधिनियम’ भी कहा गया है) और उसका समय समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे ‘नियमावली’ अथवा ‘पाटनरोधी नियमावली’ भी कहा गया है) के संबंध में;

क. इस मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 9 मई, 2014 को जापान और रूस के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये ‘फथेलिक एनहाइड्राइड’ (जिसे आगे “फेन” अथवा “संबद्ध वस्तु” अथवा “पी यू

सी” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत की और जांच करने के बाद दिनांक 3 नवंबर, 2015 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/6/2014-डी जी ए डी के माध्यम से निश्चयात्मक शुल्क लगाने की सिफारिश की। अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 04 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना सं. 56/2015 – सीमा शुल्क (ए डी डी) के माध्यम से लगाया गया था।

2. इस अधिनियम की धारा 9क (5) में अन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान है कि यदि पहले रद्द न किया गया हो तब लगाये गये पाटनरोधी शुल्क का इस प्रकार के अधिरोपण की तिथि से 5 वर्षों के समाप्त होने पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा और प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस बात की समीक्षा करें कि क्या शुल्क की समाप्ति के कारण पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। उपर्युक्त के अनुसार, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किये गये विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इस बात की समीक्षा करें कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।
3. इस नियमावली के नियम 23 (1ख) में निम्नलिखित प्रावधान हैं :
“इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई भी निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क इसके अधिरोपण की तिथि से अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी उस अवधि के समाप्त होने के पूर्व समय की उचित अवधि के भीतर घरेलू उद्योग की ओर से अथवा उसके द्वारा किये गये विधिवत प्रमाणित अनुरोध पर अथवा अपनी स्वयं की पहल पर उस अवधि के पूर्व शुरू की गई समीक्षा पर इस तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचते हों कि उक्त पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।”
4. मैसर्स आई जी पेट्रोकेमिकल्स लिमि., मैसर्स थिरुमलाई केमिकल्स लिमि. और मैसर्स एस आई ग्रुप इंडिया प्रा. लिमि. (जिसके आगे “आवेदक” अथवा “घरेलू उद्योग” भी कहा गया है) ने इस अधिनियम और इस नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की संभावना का आरोप लगाते हुए एक विधिवत प्रमाणित आवेदन दायर किया और रूस तथा जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा और उसे जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।
5. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, घरेलू उद्योग की ओर से पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ इस आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच करने के लिए दिनांक 11 मई, 2020 की अधिसूचना सं. फा. सं. 7/11/2020 – डी जी टी आर (एस एस आर सं. 06/2020) के माध्यम से निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की कि क्या उक्त शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है और क्या रूस और जापान के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के संबंध में पाटनरोधी शुल्क को लगातार लगाये रखने की आवश्यकता है।
6. वर्तमान समीक्षा के दायरे में संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पूर्व जांचों के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. प्रक्रिया

7. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन जांच के संबंध में किया गया है :
 - i. प्राधिकारी ने भारत में पाटनरोधी नियमावली के उप नियम 5(5) के अनुसार इस जांच की शुरुआत कार्यवाही करने के पूर्व वर्तमान आवेदन के प्राप्त होने के बारे में संबद्ध देशों के दूतावास को अधिसूचित किया।

- ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 11 मई, 2020 की अधिसूचना जारी की।
- iii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों के दूतावास, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को इन आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये पते के अनुसार जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत करायें।
- iv. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और दूतावास को इस आवेदन की अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।
- v. भारत में संबद्ध देशों के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर इस प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए संबद्ध देशों से निर्यातकों/ उत्पादकों को सलाह दें। इन उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावली की प्रति भी संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते के साथ उन्हें भेजी गई थी।
- vi. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों जिनके ब्यौरे आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये थे, को इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निर्यातक की प्रश्नावली भेजी।
 - क. गाजप्रोम नेफटेहिम सलावट, रूस
 - ख. जे एस सी ऊरल केमिकल कं., रूस
 - ग. वेस्ट-सिबेरियन स्टील, रूस
 - घ. अंगारस्क पैट्रोकेमिकल, रूस
 - ङ. पोलीमर पैक गो, रूस
 - च. उरलखिमप्रोम पोडलेसनया, रूस
 - छ. रोसप्लास्टोआ एल एल सी, रूस
 - ज. ओ जे एस सी कमटेक्स – हिमप्रोम, रूस
 - झ. जे ई ई केमिकल कोरपोरेशन, जापान
 - ञ. न्यू जापान केमिकल कं. लिमिटेड, जापान
 - ट. निप्पोन शोकूबाई, जापान
 - ठ. सी-गेम कं., लिमिटेड, जापान
- vii. संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
- viii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं/ प्रयोक्ता संघों जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गये थे, को जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति अग्रेषित की और उन्हें सलाह दी कि वे नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने दृष्टिकोण से अवगत करायें :
 - क. मैसर्स के एल जे प्लास्टिसाइजर्स लिमि.
 - ख. मैसर्स मजदा कलर्स लिमि.
 - ग. मैसर्स पेक ऑयल एंड सोलवेंट्स लिमि.
 - घ. मैसर्स लोनालन इंडस्ट्रीज लिमि.

- ड. मैसर्स सिलवासा प्लास्ट प्रा. लिमि.
 च. मैसर्स आरती इंडस्ट्रीज लिमि.
 छ. मैसर्स मेकहेमको इंडस्ट्रीज लिमि.
 ज. मैसर्स रचना प्लास्टिसाइजर्स
 झ. मैसर्स माइक्रो इंक्स लिमि.
 ञ. मैसर्स फथलो कलर्स एंड केमिकल्स (इं.) लिमि.
 ट. मैसर्स हेयूबच कलर प्रा. लिमि.
 ठ. मैसर्स रमनिकलाल गोसला एंड कं.
 ड. मैसर्स सनमन ट्रेड इम्पेक्स प्रा. लिमि.
 ढ. मैसर्स पेट्रोकेम मिडल ईस्ट (इंडिया) प्रा. लिमि.
 ण. मैसर्स ए-वन केम ट्रेड प्रा. लिमि.
 त. मैसर्स एमजे केमिकल्स ट्रेड प्रा. लिमि.
 थ. मैसर्स संजय केमिकल्स (इंडिया) प्रा. लिमि.
 द. मैसर्स हेजेल मर्कटाइल लिमि.
 ध. मैसर्स इंडिया प्लास्टिक्स फेडरेशन
 न. मैसर्स इंडिया प्लास्टिसाइजर्स मेनिफेक्चर्स एसो.
 प. मैसर्स इंडिया पेंट एसोसिएशन
 फ. मैसर्स केमिकल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
 ब. मैसर्स इंडियन केमिकल काउंसिल
- ix. इस उत्पाद के निम्नलिखित आयातकों अथवा उपभोक्ताओं ने निर्धारित प्रपत्र में आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है :
- क. मैसर्स के एल जे प्लास्टिसाइजर्स लिमि.
 ख. मैसर्स पायल पोलीप्लास्ट प्रा. लिमि.
- x. मैसर्स इंडियन प्लास्टिसाइजर्स मेनिफेक्चर्स एसो. (आई पी एम ए) और रूस की सरकार ने जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में भाग लेने का पत्र प्रस्तुत किया। जापान की सरकार ने भी लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया।
- xi. निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है और अथवा इस जांच से संगत सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, को गैर सहयोगी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना गया है।
- xii. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करावें।

- xiii. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर को ई-मेल करने के लिए उनमें से सभी को अनुरोध के साथ अपलोड किया गया था क्योंकि सार्वजनिक फाइल चालू वैश्विक महामारी के कारण भौतिक रूप से सुगम्य नहीं थी।
- xiv. वर्तमान समीक्षा जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि को अप्रैल 2019 से मार्च 2020 (जांच की अवधि) तक मानी गई है। वर्तमान जांच की अवधि को अप्रैल 2016 से मार्च 2017, अप्रैल 2017 से मार्च 2018 और अप्रैल 2018 से मार्च 2019 और जांच की अवधि के रूप में माना गया है। प्राधिकारी ने क्षति और पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना की जांच करने के उद्देश्य से जांच की अवधि की बाद की अवधि के रूप में अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक की अवधि भी मानी है।
- xv. अतिरिक्त/ पूरक सूचना आवेदकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों से उस सीमा तक मांगी गई थी जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया। घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों का सत्यापन जांच के उद्देश्य से उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया।
- xvi. क्षति रहित कीमत (एन आई पी) पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III और सामान्य रूप से स्वीकार किये गये लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और निर्माण तथा बिक्री करने की लागत के आधार पर है। यह सुनिश्चित करने के लिए इसे तय किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन की तुलना में कम शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xvii. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से पिछले तीन वर्षों के लिए और जांच की अवधि के लिए लेन देन वार आयात संबंधी आंकड़ों के संबंध में प्राप्त सूचना भारत में संबंधित उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य के निर्धारण के लिए अपनायी गयी है।
- xviii. इस नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 11 नवंबर, 2020 को हुई मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर दिया। मौखिक सुनवाई कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई थी। सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किये थे, से अनुरोध किया गया था कि वे विरोधी हितबद्ध पक्षकारों को उसके बाद प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से इन विचारों को लिखित अनुरोध के रूप में प्रस्तुत करें।
- xix. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान जहां कहीं भी संगत पाया गया इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों का समाधान प्राधिकारी द्वारा इन अंतिम जांच परिणामों में किया गया है।
- xx. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना दिये जाने से इनकार किया है अथवा अन्य प्रकार से नहीं दी है अथवा इस जांच में बहुत अधिक हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन अंतिम जांच परिणामों को रिकार्ड किया है।
- xxi. इस नियमावली के नियम 16 के अनुसार, इस जांच के आवश्यक तथ्यों को दिनांक 18 दिसंबर, 2020 के प्रकटन विवरण के माध्यम से ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया गया था और उन पर प्राप्त टिप्पणियों जिन्हें प्राधिकारी द्वारा संगत माना गया, का समाधान इन अंतिम जांच परिणामों में किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये प्रकटन पश्चात अधिकांश अनुरोध उनके द्वारा पूर्व में किये गये अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र है। हालांकि, प्रकटन पश्चात अनुरोधों को जिस सीमा तक संगत माना गया की जांच इन अंतिम जांच परिणामों में की जा रही है।

- xxii. इन अंतिम जांच परिणामों में *** गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और इस नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा वैसी मानी गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है।
- xxiii. जांच की अवधि के दौरान वर्तमान जांचों के लिए प्राधिकारी द्वारा ली गयी विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 71.65 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद

8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “फथेलिक एनहाइड्राइड” (पेन) है। “फथेलिक एनहाइड्राइड” (पेन) फथेलिक एसिड का एक एनहाइड्राइड है और इसका वाणिज्यिक रूप से उत्पादन ओरथे-जाइलिन अथवा नेफथालिन का उत्प्रेरक ऑक्सीडेशन द्वारा किया गया जाता है। यह एक रंगरहित ठोस पदार्थ है जिसे विभिन्न रूप में फथेलिक एनहाइड्राइड फ्लेक्स, फथेलिक एनहाइड्राइड (98 प्रतिशत न्यूनतम), फथेलिक एसिड एंड हाइड्रस, फथेलिक एनहाइड्राइड (99.8 प्रतिशत न्यूनतम) आदि कहा जाता है। फथेलिक एनहाइड्राइड के विनिर्देशों में इसकी भौतिक दिखावट, ठोस फ्लेक्स का रंग, गले हुए उत्पाद का रंग, ठोस बनाने का बिंदु, वजन से फथेलिक एनहाइड्राइड की मात्रा, अन्य एनहाइड्राइड और वजन से ऑर्गेनिक मिलावट की मात्रा और एसिडिटी सूचकांक शामिल है।

ग. 1 घरेलू उद्योग का अनुरोध

9. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये हैं :
- वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद “फथेलिक एनहाइड्राइड” फथेलिक एसिड का प्रधान वाणिज्यिक रूप है।
 - चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में है।
 - घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु का उत्पादन कर रहा है।

ग. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

10. अन्य हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

11. मूल जांच में तथा वर्तमान समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद फथेलिक एनहाइड्राइड है। पूर्व जांच में, विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा नीचे दिये गये अनुसार दी गई है। प्राधिकारी ने वर्तमान उद्देश्यों से विचाराधीन उत्पाद के उसी दायरे को माना है :

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “फथेलिक एनहाइड्राइड” है। फथेलिक एनहाइड्राइड जिसे पेन अथवा पी ए भी कहा जाता है। फथेलिक एनहाइड्राइड का एनहाइड्राइड है इसका वाणिज्यिक रूप से उत्पादन ऑर्थो-जाइलिन अथवा नेफथालियन का उत्प्रेरक आक्सीजेन द्वारा किया जाता है। यह एक रंग रहित ठोस जिसे विविध रूप में फथेलिक एनहाइड्राइड फ्लेक्स, फथेलिक एनहाइड्राइड (98 प्रतिशत न्यूनतम), फथेलिक एसिड एनहाइड्राइड, फथेलिक एनहाइड्राइड (99.8 प्रतिशत न्यूनतम) आदि भी कहा जाता है। इस उत्पाद का उत्पादन केवल एक ग्रेड में किया जाता है। अलग अलग उपयोगों के संबंध में, इसके विभिन्न प्रकारों के अंतर किये जाने योग्य रूप नहीं है। इसका प्रमुख रूप से उपयोग फथेलिक इस्टर्स के उत्पादन में किया जाता है जो प्लास्टीसाइजर्स के रूप में कार्य करता है। यह प्लास्टि उद्योग में महत्वपूर्ण रसायनिक मध्यवर्ती है, इसका उपयोग पोलियस्टर रेसिन, अल्काइड रेसिन जैसे उत्पादों के निर्माण में भी किया जाता है, जिसका उपयोग पेंट और लेक्स, असाट्रेरेटेड पोलियस्टर रेसिन, पोलियस्टर पोलियोज, डाइस और पिग्मेंट, एलोजेनेटिक एनहाइड्राइड, पोलिएथरमाइड रेसिन, इसाटोनिक एनहाइड्राइड, इंसैट रेपेलेंड्स आदि में किया जाता है।

फथेलिक एनहाइड्राइड प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अंतर्गत सीमा उपशीर्ष संख्या 29173500 के अंतर्गत वर्गीकृत एक ऑर्गेनिक रसायन है। हालांकि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

12. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयात किये गये संबद्ध वस्तु भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग, उत्पाद विनिर्देश, कीमत निर्धारण वितरण और विपणन इन वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसे विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। उसको देखते हुए, घरेलू उद्योग उत्पादन किये गये विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से आयात किये गये विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु के रूप में माना जाता है।

घ. घरेलू उद्योग और आधार

13. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

“(ख) घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

घ. 1 घरेलू उद्योग का अनुरोध

14. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के आधार और कार्यक्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

- भारत में सभी तीन उत्पादक इस जांच में भाग ले रहे हैं।
- आवेदकों ने नियम 2 (ख) के आशय से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है और वे संबद्ध देशों में किसी निर्यातक अथवा पाटित वस्तु के किसी आयातक से या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं।
- यह आवेदन इस नियमावली की आवश्यकता को पूरा करता है।

घ. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

15. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और इसके आधार के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

घ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

16. वर्तमान आवेदन मैसर्स आई जी पेट्रोकेमिकल्स लिमि., मैसर्स तिरुमलाई केमिकल्स लिमि. और मैसर्स एस आई ग्रुप इंडिया प्रा. लिमि. द्वारा दायर किया गया है। भारत में कोई अन्य मौजूदा उत्पादक नहीं है। इस कारण से आवेदक का भारत में समग्र उत्पादन है। इन आवेदकों ने निर्धारित प्रपत्र के अनुसार संगत सूचना उपलब्ध कराई है और आवेदक इस नियमावली के नियम 2(ख) के आशय से पात्र घरेलू उद्योग है। यह आवेदन इस नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंड को पूरा करता है यद्यपि नियम 5(3) के आशय से आधार को नियम 23 के अंतर्गत शुरू की गई निर्णायक समीक्षा में स्थापित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

ङ. विविध अनुरोध

ङ. 1 घरेलू उद्योग का अनुरोध

17. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किये गये हैं :

- घरेलू उद्योग का लाभ समाप्त हो गया है और घरेलू उद्योग को बहुत कम लाभ से हानि हुई है। घरेलू उद्योग द्वारा लगाये गये अधिक कीमत के आरोप की पूर्ण रूप से उपेक्षा की जानी चाहिए।
- मांग और आपूर्ति में अंतर पाटन को सही नहीं ठहरा सकता है।
- के एल जे प्लास्टिसाइजर्स लिमि. लगभग 200 के टी की क्षमता के साथ पेन संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है। ये क्षमताएं अनंतिम तौर पर 2024 तक कार्य करने लगेगी। विस्तार के बाद क्षमता भारत में अनुमानित मांग से बहुत अधिक होगी।

- iv. शुल्कों का विस्तार आयातों को नहीं रोकेगा। आयात संबद्ध देशों तथा अन्य देशों से होना जारी रह सकता है। घरेलू उद्योग को भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती जो घरेलू उद्योग की कीमतों को नियंत्रण में रखेगा।
- v. बी आई एस मानदंडों को लायेगा। यह विचार करना उचित नहीं है कि इसका उपयोग बाजार में एकाधिकार स्थापित करने के लिए किया जाता है और इस प्रकार का आरोप सरकार के कार्यचालन और निर्णय लेने के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाने के बराबर है।
- vi. घरेलू उद्योग द्वारा जांच की विभिन्न अवधि के साथ दायर किये गये आवेदन के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि निर्णायक समीक्षा तथा नये जांच के लिए आवेदन जांच की उसी अवधि में दायर किया गया है। आवेदकों ने पहले ही यह उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग को नये देशों से पाटन के कारण जांच की अवधि में क्षति हो रही है और निर्णायक समीक्षा आवेदन में संबद्ध देशों के क्षति की संभावना है।
- vii. दक्षिण कोरिया से आयातों पर द्विपक्षीय रक्षोपाय के संबंध में तर्क के बारे में यह अनुरोध किया जाता है कि द्विपक्षीय रक्षोपाय के मामले में कोरिया का आयात है जिसकी क्षति के कारक के रूप में पहचान की गई। घरेलू उद्योग सजग है और इसे इस बात की पूर्ण जानकारी है कि यह क्षति मार्जिन से आगे संरक्षित नहीं हो पायेगा।
- viii. घरेलू उद्योग को क्षति के लिए एक मात्र कारण होना आवश्यक नहीं है। प्राधिकारी को केवल इस बात का आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या पाटन और क्षति के "कारण और प्रभाव का सही और वास्तविक संबंध" है।
टेक्नोओरबीचेकबिंग के रिपोर्ट के दावे के संबंध में गोपनीय होने का दावा किया गया है। यह अनुरोध किया जाता है कि यह रिपोर्ट तीसरे पक्ष की सूचना पर आधारित है जिसे आवेदक को प्रकट करने की अनुमति नहीं है। हालांकि रिपोर्ट से लिये गये आंकड़ों को प्रकट किया गया है। ये आंकड़े हैं जो निर्धारण के लिए आधार बनेंगे।
- ix. इस दावे के संबंध में कि इस शुल्क के फलस्वरूप फथेलिक प्लास्टिसाइजर्स इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ेगा, यह अनुरोध किया जाता है कि प्रयोक्ताओं की संख्या के संबंध में कोई सूचना नहीं है कि किन प्रयोक्ताओं ने पाटनरोधी के कारण विगत में संयंत्र बंद किये हैं अथवा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई रक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया गया है।
- x. पेन की खपत डाउनस्ट्रीम उद्योग के स्वस्थ विकास को दर्शाती है जब पाटनरोधी शुल्क अथवा रक्षोपाय शुल्क लागू था। इन शुल्कों को जनहित की जांच करने के बाद लगाया गया था।

ड. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

18. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किये गये हैं :

- i. मांग और आपूर्ति में अंतर है।
- ii. भारतीय उत्पादक व्यापार उपचारात्मक उपायों का दुरुपयोग कर अधिक कीमतें वसूलते हैं।
- iii. पेन के निर्माता पाटनरोधी शुल्क, रक्षोपाय शुल्क तथा बी आई एस विनिर्देश पर बल डालकर फथेलिक एनहाइड्राइड के आयातों को रोक रहे हैं, जिससे कि वे बाजार में एकाधिकार स्थापित कर सकें।
- iv. आवेदक जांच की विभिन्न अवधियों और विभिन्न जांचों में प्राधिकारी के समक्ष क्षति के परस्पर विरोधी कारण प्रस्तुत कर रहे हैं।
- v. अत्यधिक क्षमताओं के दावे का समर्थन करने के लिए, टेक्नोओरबीकेम से एक रिपोर्ट का उपयोग किया गया है लेकिन उसे गोपनीय रखा गया है।
- vi. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने से फेथलेट प्लास्टिसाइजर्स का बहुत अधिक मात्रा में आयात का मार्ग खुल जायेगा जिसका आयात शून्य मूल सीमा शुल्क के साथ किया जा रहा है।

- vii. फथेलिक एनहाइड्राइड को फेथलेट प्लास्टिसाइजर्स में परिवर्तित करने में मूल्यवर्धन बहुत कम है और कम मूल्यवर्धन, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि के साथ यह आयात किये गये फेथलेट प्लास्टिसाइजर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जायेगा।
- viii. पाटनरोधी शुल्क के फलस्वरूप फेथलेट प्लास्टिसाइजर्स उद्योग को नीचे तक बंद करना पड़ेगा और इसके फलस्वरूप रोजगार की हानि होगी।
- ix. भारत सरकार ने पी टी ए और एक्रेलिक फाइबर के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को वापस ले लिया है जो विभिन्न क्षेत्रों के लिये प्रमुख इनपुट हैं। वही वर्तमान मामले में भी किया जाना चाहिए।
- x. चूंकि पेन हजारों लोगों को रोजगार देने वाले अनेक इकाईयों के लिए एक प्रमुख इनपुट है। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार का इनपुट उचित कीमतों पर तथा अपेक्षित मात्रा में इकाईयों को उपलब्ध कराया गया है।
- xi. प्राधिकारी को क्षमता के विस्तार की वास्तविक स्थिति पर उत्पादकों से शपथ अवश्य लेनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार के दावे अनेक हालिया जांचों में किये गये हैं लेकिन विस्तार कभी भी पूरा नहीं है।

ड. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल के माध्यम से निरीक्षण के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
20. घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के संबंध में किये गये अनुरोधों की जांच प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक की गई जिस सीमा तक उसे संगत माना गया और तदनुसार उसका समाधान किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की विधिवत जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना माना गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध करायें। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यापार संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय के रूप में दावा किया है।
21. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि देश में मांग और आपूर्ति में अंतर घरेलू उद्योग को पाटित आयातों से निवारण की मांग करने से नहीं रोकता है। मांग-आपूर्ति में अंतर पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराता है। रिकार्ड पर सूचना यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग का क्षमता विस्तार हो रहा है। वास्तव में घरेलू उद्योग ने क्षमता का विस्तार किया है और उसके प्रति निवेश किया है। इसके अलावा, दस्तावेजी साक्ष्य यह दर्शाते हुए उपलब्ध कराया गया है कि के एल जे प्लास्टिसाइजर्स लिमि. लगभग 200 के टी की क्षमता स्थापित करने की प्रक्रिया में है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि किये गये क्षमता विस्तार पर विचार करते हुए, घरेलू उद्योग की क्षमता देश में मांग की तुलना में बहुत अधिक होगी। विदेशी उत्पादक अपाटित कीमतों पर इस उत्पाद की बिक्री कर हमेशा भारतीय मांग को पूरा कर सकते हैं। पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के बाद भी, ये आयात देश में प्रतिबंधित नहीं हैं। इस कारण से यह दावा करने का कोई आधार नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप डाउनस्टीम उद्योग के लिये कच्चे माल में कमी आयेगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से समान अवसर मिलता है और यह बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को नहीं रोकता है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को भी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और उसका निर्यात अनेक देशों द्वारा किया जाता है। प्रयोक्ता किसी भी स्रोत से संबद्ध वस्तुओं का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।
22. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि व्यापार उपचारात्मक उपाय विभिन्न स्रोतों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर विगत में लगाया गया है। ये उपाय सभी हितबद्ध पक्षकारों के भाग लेने के साथ अर्ध-न्यायिक जांच करने तथा गुण अवगुण की सही जांच तथा जनहित में कानून का उचित अनुपालन और जांच के बाद लागू किया गया है। आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि की संभावना का साक्ष्य दिया है। इसके विपरीत अन्य हितबद्ध

पक्षकारों ने डाउनस्ट्रीम उत्पाद के आयातों में वृद्धि की संभावना का दावा करने के लिए कोई औचित्य/ साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। इस कारण से यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क को वर्तमान में जारी रखने के फलस्वरूप डाउनस्ट्रीम उद्योग के आयातों में वृद्धि होगी।

च. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

च. 1 सामान्य मूल्य

23. इस अधिनियम की धारा 9 क (1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

- i. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- ii. जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :-

- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो ; अथवा
- (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत ;

परंतु यह कि उदगम वाले देश से उत्तर किसी देश से वस्तु के आयात के मामले में अथवा जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश के जरिए मात्र यानांतरित किया गया है अथवा जहां ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक के देश में नहीं किया जाता है, निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

च. 2 घरेलू उद्योग का अनुरोध

24. घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में किया गया अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार है :-

- i. रूस और जापान के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की कीमतों का साक्ष्य अथवा उत्पादकों की कीमत सूची सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है।
- ii. रूस से पोलेण्ड में निर्यात का रूस से निर्यातों में सबसे अधिक हिस्सा है। उसी प्रकार से जापान से मलेशिया में निर्यातों का जापान से निर्यातों में सबसे अधिक हिस्सा है। इन दो देशों को संबद्ध देशों से निर्यात कीमतों पर विचार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए उपयुक्त रूप में किया जा सकता है।
- iii. निर्यात कीमत की गणना समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पोर्ट संबंधी खर्च और अतर्देशीय भाड़े खर्च के लिए डी जी सी आई एंड एस के लेन देन वार आंकड़ों में उचित समायोजन के बाद किया जा सकता है।
- iv. उपर्युक्त के आधार पर निर्धारित पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि बहुत अधिक है।
- v. यदि सामान्य मूल्य संरचित भी किया जाता है तब परिणामी पाटन मार्जिन बहुत अधिक है।
- vi. चूंकि संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक ने भाग नहीं लिया है। अतः पाटन मार्जिन के दावे के संबंध में कोई विवाद नहीं है।
- vii. जब शुल्क लगाया जाता है तब भी सकारात्मक पाटन इस बात की संभावना को दर्शाता है कि पाटन होता है जब शुल्क समाप्त हो जायेगा।

- viii. इस अनुरोध के संबंध में कि प्रस्तावित सामान्य मूल्य उन तथ्यों को न्यायोचित नहीं ठहराता है, यह अनुरोध किया जाता है कि प्रयोक्ता संघ केवल निष्कर्ष निकालने के बजाय संगत सूचना देने के लिए स्वतंत्र था।
- ix. उपयुक्त प्रतिनिधिक देश के संबंध में अनुरोध के बारे में संघ का यह विश्वास है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के मामले में भी प्रतिनिधिक देश की पहचान करने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता उस स्थिति में समान वस्तु का “तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत” है जब उसका निर्यात निर्यातक देश अथवा प्रक्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश में किया गया हो।

च. 3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

25. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में किया गया अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार है :-
- रूस से पोलैण्ड में सामान्य मूल्य के रूप में निर्यात कीमत पर विचार करने के लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया है।
 - दावा किये गये समायोजन के लिए सामान्य मूल्य पर पहुंचने के लिए सूचना का स्रोत नहीं दिया गया है।
 - सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू उद्योग के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्रस्तावित पद्धति न्यायोचित नहीं है।
 - पोलैण्ड और मलेशिया भारत के लिए प्रतिनिधिक देशों के रूप में माना नहीं जा सकता है।

च. 4 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना देने के लिए उन्हें सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजीं। इस जांच में किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने निर्धारित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत कर सहयोग नहीं किया है।

च. 4.1 सामान्य मूल्य का निर्धारण

रूस

27. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि रूस के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि आवेदकों ने एक उपयुक्त तीसरे देश के रूप में पोलैण्ड को मानने के लिए कोई विस्तृत औचित्य नहीं दिया है। अतः उस पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार नहीं किया गया है। इस प्रकार से प्राधिकारी ने नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

जापान

28. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जापान के किसी भी उत्पादक/ निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि आवेदकों ने एक उपयुक्त तीसरे देश के रूप में मलेशिया को मानने के लिए कोई विस्तृत औचित्य नहीं दिया है। अतः उस पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार नहीं किया गया है। इस प्रकार से प्राधिकारी ने नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

च. 4.2 निर्यात कीमत

29. चूंकि संबद्ध देशों से किसी भी उत्पादक/ निर्यातक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है अतः प्राधिकारी ने रूस और जापान के संदर्भ में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में “उपलब्ध तथ्यों” के अनुसार निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में भारित औसत आयात कीमत के आधार पर किया गया है। चूंकि यह कीमत सी आई एफ निर्यात कीमत है अतः उसका समायोजन संबंधित उत्पादकों/ निर्यातकों के द्वारा असहयोग को देखते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पोर्ट खर्च और रख-रखाव शुल्क के आधार पर किया गया है।

च. 4.3 पाटन मार्जिन की गणना

30. जैसा कि ऊपर में उल्लेख किया गया है निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, यह नोट किया जाता है कि रूस और जापान दोनों के लिए पाटन मार्जिन इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

क्र. सं.	विवरण	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	रेंज
		यू एस डॉ/ मी. ट.	यू एस डॉ/ मी. ट.	यू एस डॉ/ मी. ट.	%	%
1	जापान	***	***	***	***	20-30%
2	रूस	***	***	***	***	20-30%

छ. क्षति के निर्धारण तथा क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच के लिए पद्धति

31. अनुबंध - II के साथ पठित इस नियमावली नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए...” घरेलू उद्योग की क्षति को दर्शाते वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में हास होता अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक हद तक हुई होती।
32. इस नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19 और 20 के प्रावधान किसी समीक्षा के मामले में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। प्राधिकारी ने अपनी जांच में क्षति संबंधी मानदंडों का मूल्यांकन किया है जो इस नियमावली के नियम 11 और अनुबंध II के अंतर्गत अपेक्षित है और इसने इस तथ्य की भी जांच की है कि क्या शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।
33. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदन मैसर्स आई जी पेट्रोकेमिकल्स लिमि., मैसर्स तिरुमलाई केमिकल्स लिमि. और मैसर्स एस आई ग्रुप इंडिया प्रा. लिमि. द्वारा दायर किया गया है। इस नियमावली के नियम 2 (ख) के संबंध में, आवेदकों को इस जांच के उद्देश्य से घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है। इस कारण से आवेदकों को नियम 2(ख) में यथा परिभाषित घरेलू उद्योग हैं, की लागत और क्षति संबंधी सूचना की जांच की गई है।

छ. 1 घरेलू उद्योग का अनुरोध

34. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग का अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार है:
- संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने और अन्य देशों से पाटन के कारण क्षति की अवधि में गिरावट आई है।
 - घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति संबद्ध देशों से आयातों के कारण नहीं हुई है।
 - घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है और जैसे ही क्षमता का विस्तार किया जायेगा घरेलू उद्योग देश में इस उत्पाद की संपूर्ण मांग को पूरा करने में सक्षम होंगे।
 - योजना बनाई गई और किये गये बहुत अधिक निवेशों पर विचार करते हुए, यह आवश्यक है कि भारतीय बाजार को पाटन का अनुचित व्यापार कार्यपद्धति से सुरक्षा प्रदान की जाये।

- v. उद्योग उद्योग के कार्य निष्पादन में क्षति की वर्तमान अवधि के दौरान उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री, माल सूची, बाजार हिस्सा, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ जैसे मानदंडों के संबंध में गिरावट आई है।
- vi. घरेलू उद्योग को मांग और आपूर्ति में अंतर के बावजूद जांच की अवधि में निष्क्रिय क्षमताओं का सामना करना पड़ा था।
- vii. घरेलू उद्योग को बिक्री में गिरावट के कारण हानि हुई और माल सूची के जमा होने की स्थिति का सामना करना पड़ा।
- viii. बहुत अधिक उच्च माल सूची और मांग में कमी का सामना करते हुए घरेलू उद्योग को बहुत कम कीमतों पर बहुत अधिक निर्यात करना पड़ा था।
- ix. घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में न केवल अपनी बिक्री संबंधी अवसरों बल्कि मार्जिन पर भी समझौता करना पड़ा था।
- x. उत्प्रेरक प्रत्येक 27-30 महीने में बदल जाता है। वह वर्ष जिसमें इसमें परिवर्तन होता है, कच्चे माल और यूटिलिटी के उत्पादन और उपयोगिता के संयंत्र में बहुत अधिक कार्य क्षमता देखी जाती है जो बाद में गिरना शुरू हो जाता है। इस कारण से क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिये ऐसे एक वर्ष के लिए उच्चतर उत्पादन और कमतर खपत पर विचार करना उपयुक्त होगा।
- xi. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में वर्तमान गिरावट अधिकांश रूप से चीन, इण्डोनेशिया, कोरिया गणराज्य और थाइलैण्ड से पाटन के कारण हुआ था। इसके बावजूद यह पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना सिद्ध करता है।
- xii. घरेलू उद्योग अपनी निष्क्रिय क्षमताओं, उच्च माल सूची के साथ कार्य कर रहा है और यह बहुत अधिक मात्राओं का निर्यात करने के लिए विवश था। ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों यह ग्राहक के प्रश्नों का उत्तर देना रोक देगा यदि प्रत्याशित कीमतें बहुत अधिक कम और अनुचित हैं।
- xiii. क्षति के मार्जिन की तुलना भाड़े को जोड़कर की जा सकती है क्योंकि ग्राहक अपनी खरीद के बारे में निर्णय लेते हैं और अपने फैक्ट्री वेयरहाउस में आयातों की पहुंच कीमत की तुलना के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं के साथ कीमत के बारे में मोल भाव करते हैं।
- xiv. जहां तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध का प्रश्न है कि नकारात्मक कीमत कटौती घरेलू उद्योग द्वारा वसूली जाने वाली उच्च कीमत को दर्शाता है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि नकारात्मक कीमत कटौती का अर्थ यह है कि घरेलू उद्योग की कीमतें आयात की कीमतों से कमतर थीं। इसके अलावा, यदि घरेलू उद्योग ने उच्चतर कीमत वसूली होती तब घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी नहीं आई होती और वह प्रतिकूल नहीं हुआ होता।
- xv. आवेदकों ने आवेदन में स्पष्ट रूप से यह लिखा है कि वे भाड़े को जोड़कर ग्राहक के स्तर पर एन आई पी का निर्धारण करने का अनुरोध नहीं कर रहे हैं। एन आई पी का निर्धारण एक्स फैक्ट्री स्तर पर किया जा सकता है। हालांकि, क्षति के मार्जिन का निर्धारण संबद्ध भाड़े को जोड़कर किया जाना चाहिए। ग्राहकों ने आवेदक के दावे का विरोध नहीं किया है।
- xvi. जहां तक ओ एक्स के कारण क्षति के दावे का प्रश्न है, यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान कच्चे माल की उपलब्धता में किसी मुद्दे का सामना नहीं करना पड़ा है। यह प्रतिवादी का अपना दावा है कि कच्चा माल शून्य सीमा शुल्क पर उपलब्ध है। घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को कच्चे माल के अनुरूप करने की आवश्यकता है लेकिन यह पाटित आयातों के कारण वैसा नहीं कर सका।
- xvii. निर्यात में प्रतिकूल कार्य निष्पादन देश में पाटित आयातों के कारण क्षति के आधार पर हुआ है और इसे घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों में से एक कारक के रूप में माना जा सकता था।

- xviii. जहां तक इस दावे का प्रश्न है कि घरेलू उद्योग को लाभ मिलता है, यह अनुरोध किया जाता है कि जब घरेलू उद्योग के पास ये “लाभ” भी हैं, तब इसका कार्य निष्पादन खराब है जो पाटित आयातों के कारण जोखिम को दर्शाता है।
- xix. जहां तक टी सी एल संयंत्र के संबंध में अनुरोध का प्रश्न है यह अनुरोध किया जाता है कि प्रौद्योगिकी में सतत् रूप से निवेश करना और कार्यक्षमता में सुधार लाना रीति के अनुसार है। वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये विवरण ऐसे किये गये प्रौद्योगिकी निवेशों के संदर्भ में है। सभी अर्थों में टी सी एल का तकनीकी कार्य निष्पादन वैश्विक स्तर पर अन्य उत्पादकों के समतुल्य है।

छ. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

35. क्षति और कारणात्मक संबद्ध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार है :

- i. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों के अधिकांश कारक यह दर्शाते हुए सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो रही है और बहुत अधिक शुल्क को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।
- ii. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन को चीन जन. गण., इण्डोनेशिया, कोरिया गणराज्य, थाइलैण्ड और ताइवान से कम कीमत पर आयातों के बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण हानि हुई है।
- iii. आवेदकों ने यह माना है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात के कारण कोई लगातार क्षति नहीं हुई।
- iv. ऑर्थोजाइलीन और अंतिम उत्पाद के बीच कीमत में अंतर और ऑर्थोजाइलीन की उपलब्धता का भारत में पेन के निर्माताओं के कार्य निष्पादन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।
- v. घरेलू उद्योग एक नियमित निर्यातक है जो भारत में मांग और आपूर्ति की स्थिति को प्रभावित करता है। निर्माता क्षति के किसी प्रकार का दावा किये बिना घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में कमतर कीमत पर विदेश में पेन की बिक्री कर रहा है।
- vi. क्षति रहित कीमत और पहुंच कीमत दोनों में क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए भाड़े को जोड़ने का प्रस्ताव अनुबंध III के विरुद्ध है।
- vii. आवेदक ने नकारात्मक मार्जिन को शून्य कर लेन देन वार डी एम/ आई एम प्रस्तुत किया है जो प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई पद्धति नहीं है।
- viii. आयात के प्रमुख स्रोतों की पहले ही व्यापार उपायों के अंतर्गत जांच की गई है। संबद्ध देशों से मामूली आयात को पाटनरोधी शुल्क से मुक्त किया जाना चाहिए।
- ix. टी सी एल बहुत पुराने संयंत्र और प्रौद्योगिकी के साथ कार्य कर रहा है जिसके कारण बार बार शटडाउन करना चाहता है और अन्य मुद्दे भी उत्पन्न होते हैं। क्षति ऐसे कारकों के कारण होती है।
- x. उत्पादकों का अन्य कारण है जो उनके कार्य निष्पादन पर प्रभाव डाल रहा है लेकिन व्यापार उपचारात्मक उपायों का अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उन्हें उनके लिए आयात को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।
- xi. घरेलू उद्योग को कच्चे माल के आयातों पर शून्य उर्जा लागत और सीमा शुल्क के लाभ के कारण सहज लाभ मिलता है। इस कारण उन्हें क्षति नहीं उठानी पड़ सकती है।
- xii. पेन के निर्माता ग्राहक के पूछताछ का जवाब नहीं दे रहे हैं और वे एकपक्षीय रूप से उच्च कीमते लगा रहे हैं।
- xiii. संबद्ध देशों से आयात भारतीय मांग का केवल 1 प्रतिशत था जो इस प्रकार के आयातों की नगण्यता को दर्शाता है।
- xiv. जापान से आयात क्षति की समग्र अवधि में 3 प्रतिशत की आरंभिक सीमा से कम पर हुई है और इस कारण से जापान को बाहर रखा जाना चाहिए।

छ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

36. प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों को नोट किया है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) समान वस्तु के लिये घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव और पाटित आयातों की मात्रा; तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव दोनों का वस्तुपरक जांच का प्रावधान है।
37. सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9(क)(5) के अनुसार, यदि पूर्व में पाटनरोधी शुल्क को वापस नहीं लिया गया हो तब लगाया गया पाटनरोधी शुल्क ऐसे अधिरोपण की तिथि से पांच वर्षों के समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो जायेगा बशर्ते कि केंद्र सरकार किसी समीक्षा में इस मत की हो कि इस प्रकार के शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है, यह आगे के पांच वर्षों की अवधि के लिए ऐसे अधिरोपण की अवधि का समय समय पर विस्तार कर सकती है और इस प्रकार कि आगे की अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तिथि से शुरू होगी।
38. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच करने के लिए कार्यवाही करने के पूर्व घरेलू उद्योग को वर्तमान क्षति, यदि कोई हो की जांच करने की कार्यवाही करते हैं।
39. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मानदंड गिरावट को दर्शाते हों। कुछ मानदंड गिरावट को दर्शा सकते हैं जबकि कुछ अन्य मानदंड गिरावट को नहीं दर्शा सकते हैं। प्राधिकारी क्षति संबंधी सभी मानदंडों पर विचार करते हैं और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क्या घरेलू उद्योग को पाटन के कारण क्षति हुई है अथवा क्षति होने की संभावना है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों और तथ्यों पर वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार करते हुए क्षति के मानदंडों की जांच की है।
40. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों पर विचार करते हुए उसका विश्लेषण किया है। बाद के पैराओं में प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति संबंधी विश्लेषण घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों का समाधान करता है।

छ. 3.1 मांग का आकलन

41. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग और स्पष्ट खपत का निर्धारण भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में की है।

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. ट.	2,23,200	2,35,591	2,37,924	2,28,046
2	अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी. ट.	24,000	6,000	-	-
3	संबद्ध देशों से आयात	मी. ट.	5,866	10,037	11,171	5,732
4	अन्य देशों से आयात	मी. ट.	86,184	1,20,402	1,33,488	1,68,723
5	कुल मांग/ खपत	मी. ट.	3,39,251	3,72,030	3,82,583	4,02,500

42. यह देखा जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान सतत् रूप से वृद्धि हुई है।

छ. 3.2 पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

I. संबद्ध देशों का आयात संबंधी मात्रा और हिस्सा

43. संबद्ध देशों से पाटित आयातों तथा अन्य देशों से आयातों की मात्रा के प्रभाव की जांच प्राधिकारी द्वारा की गई है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	संबद्ध देश	मी. ट.	5,866	10,037	11,171	5,732
क	जापान	मी. ट.	350	-	-	300
ख	रूस	मी. ट.	5,516	10,037	11,171	5,432
2	अन्य देश	मी. ट.	86,184	1,20,402	1,33,488	1,68,723
3	कुल	मी. ट.	92,051	1,30,439	1,44,660	1,74,454
4	निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध देशों से आयात -					
क	भारतीय उत्पादन	%	1.98%	3.47%	4.06%	2.13%
ख	मांग	%	1.73%	2.70%	2.92%	1.42%
ग	कुल आयात	%	6.37%	7.69%	7.72%	3.29%

44. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों की मात्रा में 2018-19 तक वृद्धि हुई लेकिन उसके बाद जांच की अवधि में उसमें तेजी से गिरावट आई है।

छ. 3.3 पाटित आयातों का मात्रा संबंधी प्रभाव

45. इस नियमावली के अनुबंध II (ii) के संबंध में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो के संदर्भ में घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करें।

क. कीमत में कटौती

46. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमत में बहुत अधिक हद तक कमी आती अथवा कीमत में वृद्धि रुक जायेगी जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती। इस संबंध में संबद्ध देशों से उत्पाद का पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत, व्यापार की उसी स्तर पर सभी छूट और करों का निवल के बीच तुलना की गई है।

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
2	समग्र रूप में संबद्ध देश					
क	पहुंच कीमत	रु./ मी. ट.	53,098	66,901	73,712	65,562
ख	कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
ग	कीमत में कटौती	%- रेंज	20-30%	0-10%	0-10%	0-10%
3	जापान					
क	पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	51,027	-	-	60,985

ख	कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***	-	-	***
ग	कीमत में कटौती	%- रेंज	30-40%	-	-	10-20%
4	रूस					
क	पहुंच मूल्य	रु./ मी. ट.	53,230	66,901	73,712	65,815
ख	कीमत में कटौती	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
ग	कीमत में कटौती	%- रेंज	20-30%	0-10%	0-10%	0-10%

47. यह देखा जाता है कि दोनों देशों से आयातों के संबंध में कीमत में कटौती सकारात्मक है।

ख. कीमत हास/ न्यूनीकरण

48. यह निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतें कम हो रही है अथवा उस पर दबाव पड़ रहा है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों में बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जायेगी जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती, प्राधिकारी क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तनों को नोट करते हैं।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	बिक्री की लागत	रु./मी. ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	117	113
2	बिक्री कीमत	रु./मी. ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	119	101
3	संबद्ध देशों से पहुंच कीमत	रु./मी. ट.	53,098	66,901	73,712	65,562
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	126	139	123

49. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत दोनों में जांच की अवधि में गिरावट आई है। हालांकि, बिक्री कीमत में गिरावट बिक्री की लागत में गिरावट से बहुत अधिक है। जांच की अवधि ने भी आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट देखी है। हालांकि संबद्ध देशों से जांच की अवधि में किया गया मामूली आयात पर विचार करते हुए, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट के लिए आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है। इस कारण से, जबकि घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है वे संबद्ध देशों से आयातों के कारण नहीं हुए हैं।

ग. कम कीमत पर बिक्री

50. कम कीमत पर बिक्री का मूल्यांकन क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से करते हुए की गई है।

क्र. सं.	विवरण	क्षति रहित कीमत (एन आई पी)	पहुंच कीमत	कम कीमत पर बिक्री	कम कीमत पर बिक्री	कम कीमत पर बिक्री का रेंज
		रु./ मी. ट.	रु./ मी. ट.	रु./ मी. ट.	%	%
1	जापान	***	60,985	***	***	0-10%

2	रूस	***	65,815	***	***	0-10%
---	-----	-----	--------	-----	-----	-------

51. यह देखा जाता है कि दोनों संबद्ध देशों से पाटित आयातों के संबंध में कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है।

ख. 3.3 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों पर प्रभाव

52. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-11 में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। पाटनरोधी नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक मापदंडों और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का तथ्यपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है :-

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री

53. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	क्षमता	मी. ट.	3,17,110	3,17,110	3,17,110	3,17,110
2	उत्पादन	मी. ट.	2,72,561	2,83,491	2,75,492	2,69,640
3	क्षमता का उपयोग	%	86%	89%	87%	85%
4	घरेलू बिक्री	%	2,23,200	2,35,591	2,37,924	2,28,046

54. यह नोट किया जाता है कि -

- क. घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की पूरी अवधि के दौरान स्थिर रही है।
- ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2017-18 तक वृद्धि हुई है लेकिन उसके बाद उसमें गिरावट आई है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद की घरेलू बिक्री 2018-19 तक बढ़ी है लेकिन जांच की अवधि के दौरान उसमें कमी आई है।

ख. मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा

55. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभावों की जांच की गई है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग	%	66%	63%	62%	57%
2	अन्य उत्पादक	%	7%	2%	0%	0%
3	संबद्ध देश	%	2%	3%	3%	1%
4	अन्य देश	%	25%	32%	35%	42%

56. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग और संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है। अन्य देशों ने बाजार हिस्से में बहुत अधिक वृद्धि देखी है।

ग. माल सूची

57. प्राधिकारी ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री की मात्रा पर विचार किया है।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	औसत माल सूची	मी. ट.	5,904	3,564	3,429	4,934

58. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की औसत माल सूची के स्तर ने 2018-19 तक गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी है और उसके बाद जांच की अवधि में उसमें वृद्धि हुई है।

घ. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर लाभ

59. घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर लाभ के संबंध में की गई है।

क्र. सं.	विवरण	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	बिक्री की लागत	₹/ मी. ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	117	113
2	बिक्री कीमत	₹/ मी. ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	119	101
3	लाभ / हानि	₹/ मी. ट.	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	203	138	4
4	लाभ / हानि	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	215	147	4
5	नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	198	143	23
6	ब्याज और कर पूर्व लाभ	₹लाख	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	197	139	15
7	लगाई गई पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	150	106	11

60. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग को पिछले वर्ष तक अच्छा लाभ मिल रहा था। हालांकि, घरेलू उद्योग के लाभ में जांच की अवधि में तेजी से गिरावट आई है। इसके परिणामस्वरूप, नकद लाभ और निवेश पर लाभ भी प्रभावित हुआ है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

61. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति की जांच की गई थी।

क्र. सं.	विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	कर्मचारियों की संख्या	सं.	695	757	783	775
2	वेतन एवं मजदूरी	₹ लाख-प्रवृत्ति	100	121	127	130
3	प्रतिदिन उत्पादकता	मी. ट./ दिन	779	810	787	770
4	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. ट./ सं.	392	374	352	348

62. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तरों में क्षति की अवधि के दौरान उतार चढ़ाव रहा है और भुगतान की गई मजदूरी में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। प्रति कर्मचारी और प्रति दिन उत्पादकता में 2017-18 में वृद्धि हुई लेकिन उसके बाद उत्पादन में गिरावट आई है।

च. वृद्धि

63. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के वृद्धि संबंधी मानदंडों की जांच नीचे दर्शायी गई है -

क्र. सं.	विवरण	यू ओ एम	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि
1	उत्पादन	वाई/ वाई	-	4%	-3%	-2%
2	उत्पाद का उपयोग	वाई/ वाई	-	4%	-3%	-2%
3	घरेलू बिक्री	वाई/ वाई	-	6%	1%	-4%
4	लाभ/ (हानि) प्रति इकाई	वाई/ वाई	-	103%	-32%	-97%
5	माल सूची	वाई/ वाई	-	-40%	-4%	44%
6	बाजार का हिस्सा	वाई/ वाई	-	-4%	-2%	-9%
7	लाख रु. में लाभ/ (हानि)	वाई/ वाई	-	115%	-31%	-98%
8	लाख रु. में नकद लाभ	वाई/ वाई	-	98%	-28%	-84%
9	ब्याज और कर पूर्व लाभ लाख रु. में	वाई/ वाई	-	97%	-29%	-89%
10	निवेश पर लाभ %	वाई/ वाई	-	50%	-29%	-90%

64. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन संबंधी अधिकांश मानदंड जांच की अवधि में नकारात्मक वृद्धि को दर्शाते हैं।

छ. पाटन का परिमाण

65. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों में पाटन मार्जिन न केवल सकारात्मक है बल्कि बहुत अधिक भी है।

ज. नए निवेश जुटाने की क्षमता

66. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर विचार करते हुए, यह देखा जाता है कि नये निवेश जुटाने की कंपनी की क्षमता कमजोर होने की संभावना है। यदि घरेलू उद्योग को इन स्तरों पर लाभ मिल रहा हो।

झ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

67. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत प्रभावित हुई है क्योंकि यह समुचित लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं है। संबद्ध देशों से आयात वह कारक नहीं है जो घरेलू कीमतों को प्रभावित करता हो।

ञ. क्षति के संबंध में टिप्पणियां

68. वास्तविक क्षति के संबंध में विभिन्न मानदंडों पर विचार करते हुए, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग को समग्र कार्य निष्पादन खराब है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में स्वतंत्र रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में तेजी से गिरावट आई है। घरेलू बिक्री कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव मौजूद है लेकिन इसे पाटित आयातों का कारण नहीं माना जा सकता है। घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में क्षमता का उपयोग, उत्पादन, बिक्री, बाजार का हिस्सा, लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ के मामले में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को क्षति हुई है और घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक है।

ज. कारणात्मक संबंध

69. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों के अलावा किसी ज्ञात कारकों की जांच करें जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं अथवा क्षति पहुंचाने की संभावना है ताकि इन अन्य कारकों द्वारा हुई क्षति का कारण पाटित आयातों को नहीं माना जा सकता है। जबकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और कारणात्मक संबंध की पहले की जांच मूल जांच में की जा चुकी है, प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है अथवा होने की संभावना है। यह जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारक घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान कर सकता था अथवा योगदान करने की संभावना है।

क. तीसरे देश से आयातों की मात्रा और कीमत

70. यह देखा जाता है कि चीन, इण्डोनेशिया, कोरिया गणराज्य, थाइलैण्ड और ताइवान से आयातों की मात्रा न्यूनतम सीमाओं से ऊपर हैं। आवेदक ने यह दावा किया कि इन देशों से आयात पाटित कीमतों पर हुआ है। प्राधिकारी ने दिनांक 21 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या 6/16/2020 के माध्यम से चीन, इण्डोनेशिया, कोरिया गणराज्य और थाइलैण्ड से आयातों के संबंध में जांच शुरू की है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने कोरिया गणराज्य से आयातों पर भुगतान किये जाने वाले सीमा शुल्क पर रियायत को समाप्त कर द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश की है। ताइवान से आयात घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से ऊपर है और इस कारण से यह घरेलू उद्योग को क्षति का एक कारण नहीं हो सकता है।

ख. मांग में संकुचन और/ अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन

71. संबद्ध वस्तुओं की मांग में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस कारण से खपत के पैटर्न में परिवर्तन घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान नहीं कर सकता था।

ग. प्रौद्योगिकी का विकास

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस कारण से प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का एक संभावित कारक नहीं है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धतियां

73. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई व्यापार कार्य प्रतिबंधात्मक कार्यपद्धति नहीं है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

ड. निर्यात कार्य निष्पादन

74. आवेदक ने यह तर्क दिया है कि यह घरेलू बाजार में पाटित आयातों के कारण जांच की अवधि में निर्यात करने के लिए बाध्य रहा है। आवेदक ने यह तर्क दिया कि मात्रा और कीमत दोनों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किये गये निर्यात को इस देश में पाटन के परिणाम के रूप में माना जाना चाहिए। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की निर्यात बिक्री में जांच की अवधि में तेजी से वृद्धि हुई है और निर्यात में लाभप्रदता घरेलू बिक्री की तुलना में बहुत कम थी। घरेलू उद्योग को निर्यातों में वित्तीय हानि उठानी पड़ी है। जबकि प्राधिकारी ने घरेलू और निर्यात प्रचालनों के लिए घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी विश्लेषण के उद्देश्य से उस सीमा तक अलग अलग किये गये आंकड़ों पर विश्वास किया है जिस सीमा तक ऐसा किया जा सकता था, यह तथ्य कि घरेलू उद्योग बहुत अधिक कम और अलाभप्रद कीमतों पर निर्यात करने के लिए विवश था, घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है। इसके अलावा, चूंकि निर्यात मात्राओं और लाभों को अलग अलग कर दिया गया है अतः निर्यात कार्य निष्पादन में संभावित गिरावट इसमें ऊपर मानी गई क्षति का कारण नहीं है।

च. अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन

75. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के कार्य निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इस कारण से उत्पादन किये गये अन्य उत्पादों और आवेदकों द्वारा बेचे गये अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभावित कारण नहीं है।

झ. क्षति मार्जिन का परिमाण

76. क्षति मार्जिन का मूल्यांकन संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से क्षति रहित कीमत की तुलना कर किया गया है।

क्र. सं.	विवरण	क्षति रहित कीमत (एन आई पी)	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	रेंज
		रु. / मी. ट.	रु. / मी. ट.	रु. / मी. ट.	%	%
1	जापान	***	60,985	***	***	0-10%
2	रूस	***	65,815	***	***	0-10%

77. यह देखा जाता है कि दोनों संबद्ध देशों से पाटित आयातों के संबंध में क्षति मार्जिन सकारात्मक है।

ब. क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना

78. समीक्षा जांच में प्राधिकारी को यह निर्धारण करना है कि क्या संबद्ध वस्तु पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में आ रही हैं अथवा आने की संभावना है और क्या घरेलू उद्योग को क्षति, यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तब इन पाटित आयातों के कारण जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है।

ब. 1 घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

79. क्षति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोधों को इसमें आगे फिर से दिया गया है :
- दोनों संबद्ध देशों में उत्पादक वर्तमान में निष्क्रिय क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं।
 - दोनों संबद्ध देशों में उत्पादन के प्रतिशत के रूप में मांग बहुत अधिक कम है जो यह दर्शाता है कि बहुत अधिक उत्पादन निर्यात के लिये किया गया है।
 - तीसरे देशों को बहुत अधिक निर्यात पाटित और क्षति कारक कीमतों पर हुआ है।
 - उन आयातों जो पाटित और क्षति कारक कीमतों पर हुए हैं की मात्रा भारतीय मांग का बहुत बड़ा हिस्सा है।

- v. निर्यातों की बहुत अधिक मात्रा है जिसे भारत की ओर भेजा जा सकता है क्योंकि शुल्कों को वापस लिये जाने की स्थिति में भारतीय बाजार आकर्षक हैं।
- vi. अगले तीन वर्षों में क्षमता और उत्पादन के लिए भावी अनुमान यह दर्शाता है कि दोनों देशों में क्षमताएं निष्क्रिय रहेगी।
- vii. भारत विगत में रूस के उत्पादकों के लिए एक प्राथमिक बाजार रहा है क्योंकि इसके पास निर्यातों में लगभग 34 प्रतिशत हिस्सा है।
- viii. जापान से आयातों पर रियायती शुल्क लगता है और प्रयोक्ताओं को जापान से आयात करने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- ix. यदि घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से आयातों की कीमत के अनुरूप अपनी कीमत रखने के लिए बाध्य होते हैं तब इसे बहुत अधिक हानि और नकारात्मक लाभ मिलेगा।
- x. पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत में कटौती दोनों संबद्ध देशों के मामले में सकारात्मक है जो क्षति की संभावना को दर्शाता है।
- xi. जापान और रूस दोनों से आयातों की पहुंच कीमत चीन, इण्डोनेशिया, कोरिया गणराज्य और थाइलैण्ड से आयातों की पहुंच कीमत से तर्कसंगत रूप से कम है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।
- xii. जापान से जांच की बाद की अवधि में आयातों की मात्रा क्षति की वर्तमान अवधि पर विचार करते हुए उच्चतम स्तर पर है।
- xiii. रूस से आयातों ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में बहुत अधिक उछाल दर्ज किया है।
- xiv. जांच की अवधि की बाद की अवधि में बढ़ता हुआ आयात भी घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना है।
- xv. दोनों देशों से आयात जांच की अवधि की बाद की अवधि में न्यूनतम सीमाओं से ऊपर है (यद्यपि न्यूनतम का प्रावधान समीक्षा के मामले में लागू नहीं होता है)। कच्चे माल की कीमतों में संचलन की जांच किये बिना कीमतों में केवल वृद्धि भ्रामक है।
- xvi. इस अनुरोध के संबंध में की संबद्ध आयात शुल्कों की सिफारिश किये जाने के पूर्व आयातों का कभी भी एक प्रमुख स्रोत नहीं था, यह अनुरोध किया जाता है कि दोनों संबद्ध देशों से आयात न्यूनतम सीमाओं से ऊपर था, जिसके फलस्वरूप वर्तमान शुल्क लगाना पड़ा।
- xvii. वास्तव में काफी संख्या में तीसरे देशों को औसत निर्यात कीमत का कोई अभिप्राय नहीं है क्योंकि इनकी कीमतों के बारे में निर्णय अलग अलग बिक्री लेन देन के लिए किया जाता है और भारित औसत केवल तोड़ी मरोड़ी गई तस्वीर को प्रस्तुत करेगा। इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि की बाद की अवधि में अपनी कीमतों में वृद्धि की है, यह अनुरोध किया जाता है कि कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

ब. 2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध

80. क्षति की संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को इसमें नीचे फिर से दिया गया है :

- i. आवेदकों ने यह माना है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात के कारण कोई सतत् क्षति नहीं हुई।
- ii. संबद्ध देशों के आयातों का हिस्सा नगण्य है और इस शुल्क को समाप्त किये जाने की आवश्यकता है।
- iii. संबद्ध देशों से कीमतों में जांच की अवधि में 49.37 रु. प्रति किलोग्राम से 60.76 रु. प्रति किलोग्राम तक वृद्धि हुई है।
- iv. मात्रा में कमी और कीमत में वृद्धि यह दर्शाती है कि निर्यातक कमतर कीमतों पर निर्यात करने के लिए किसी दबाव के अधीन नहीं हैं।

- v. वर्तमान मामले में कीमत में सकारात्मक कटौती घरेलू उद्योग द्वारा वसूली गई बहुत अधिक कीमत के कारण हो सकती है।
- vi. पेन का विश्व में एक संतुलन मांग आपूर्ति की स्थिति है और संबद्ध देश आपूर्ति के प्रमुख स्रोत नहीं हैं।
- vii. संबद्ध देश पाटनरोधी शुल्क लगाये जाने के पूर्व आयात के प्रमुख स्रोत नहीं थे। यदि आयात शुल्क पूर्व स्तर पर भी चला जाता है तब यह बहुत नगण्य होगा।
- viii. तीसरे देशों से निर्यातों पर क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन एक भ्रामक स्थिति दर्शाती है।
- ix. जांच की अवधि की बाद की अवधि में घरेलू उद्योग का कार्य निष्पादन बहुत मजबूत है और आई जी पी एल तथा टी सी एल के प्रकाशित परिणाम लाभ में बहुत अधिक वृद्धि को दर्शाते हैं।
- x. घरेलू बाजार में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमत में कच्चे माल की कीमतों में किसी अनुपातिक वृद्धि के बिना 25 से 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।
- xi. संभावना के दावे की पुष्टि नहीं की गई है।

अ. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

81. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध – II (vii) तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड पर लाये गये अन्य संगत कारकों के संदर्भ में वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों तथा धारा 9क (5), नियम 23 के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकता पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना की जांच की है। प्राधिकारी निम्नानुसार नोट करते हैं।
82. वर्तमान जांच जापान और रूस से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाये गये शुल्कों की एक निर्णायक समीक्षा है। इस निमयावली के अंतर्गत प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य का निर्धारण करें कि क्या मौजूदा शुल्क को समाप्त करने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने अन्य संगत कारकों की भी जांच की है जिसका घरेलू उद्योग को पाटन के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा परिणामी क्षति की संभावना पर प्रभाव पड़ सकता था।
83. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदकों ने संबद्ध देशों में क्षमताओं, उत्पादन और मांग के संबंध में सूचना के लिए टेक्नोओरबीकेम रिपोर्ट पर विश्वास किया है। संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक ने इस जांच में भाग नहीं लिया है और अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग द्वारा किये गये दावे का खण्डन करते हुए कोई न्यायोचित सूचना/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि रूस की सरकार ने वर्तमान जांच में भाग लिया है, फिर भी उनके द्वारा पाटन के फिर से जारी रहने अथवा उसके फिर से होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के संबंध में कोई सत्यापन योग्य सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

अ. 3.1 संबद्ध देशों में क्षमताएं

84. उपयोग न की गई क्षमताओं के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :

क्र. सं.	विवरण	2016	2017	2020	2023
1	क्षमता (के टी में)	457	457	457	457
क	रूस	282	282	282	282
ख	जापान	175	175	175	175
2	उत्पादन (के टी में)	274	282	299	309
क	रूस	124	131	139	144
ख	जापान	150	151	160	165
3	उपयोगिता % में	60%	62%	65%	68%
क	रूस	44%	46%	49%	51%

ख	जापान	86%	86%	92%	94%
4	निष्क्रिय क्षमताएं	183	175	158	149
क	रूस	158	151	143	138
ख	जापान	25	24	15	11

85. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों की बहुत अधिक क्षमताओं का रूस के मामले में उपयोग नहीं किया गया है जबकि इन क्षमताओं का बहुत अधिक हद तक उपयोग जापान के मामले में किया गया है। इसके अलावा, अगले कुछ वर्षों के लिए अनुमान दर्शाते हैं कि रूस में क्षमताएं बहुत अधिक हद तक उपयोग न की गई रह जायेगी, जबकि जापान में क्षमताओं का उपयोग बढ़ता हुआ रहेगा।

अ. 3.2 निर्यात उन्मुखीकरण

86. संबद्ध देशों में मांग की तुलना में अतिरिक्त उत्पादन के संबंध में सूचना नीचे दिये गये अनुसार है :

क्र. सं.	विवरण	2016	2017	2020	2023
1	कुल उत्पादन (के टी में)	274	282	299	309
क	रूस (के टी में)	124	131	139	144
ख	जापान (के टी में)	150	151	160	165
2	कुल खपत (के टी में)	193	195	201	207
क	रूस (के टी में)	88	89	95	99
ख	जापान (के टी में)	105	105	106	109
3	उत्पादन के % के रूप में खपत	70%	69%	67%	67%
क	रूस	71%	68%	68%	69%
ख	जापान	70%	70%	66%	66%
4	क्षमता के % के रूप में खपत	42%	43%	44%	45%
क	रूस	31%	32%	34%	35%
ख	जापान	60%	60%	61%	62%

87. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों में मौजूदा मांग उत्पादन का 70 प्रतिशत से कम है। इसके अलावा, क्षमता के प्रतिशत के रूप में खपत रूस में कम है जबकि वह जापान के मामले में अधिक है।

अ. 3.3 तीसरे देश को पाटन और क्षति

88. नीचे दी गई तालिका पाटित, आकर्षिक और क्षति रहित कीमतों पर इन निर्यातकों के द्वारा तीसरे देशों को निर्यातों की मात्रा दर्शाती है।

क्र. सं.	विवरण	रूस से तीसरे देश को निर्यात	जापान से तीसरे देश को निर्यात
1	एन आई पी से कम मात्रा	29,259	36,662
2	एन आई पी से कम मात्रा	26,953	8,185
3	सामान्य मूल्य से कम मात्रा	47,638	44,484
4	सामान्य मूल्य से कम मात्रा	8,573	363

5	भारतीय कीमतों से कम मात्रा	37,244	42,111
6	भारतीय कीमतों से कम मात्रा	18,968	2,736
7	भारत में मांग	4,02,500	4,02,500
8	मांग की तुलना में निर्यात		
क	सामान्य मूल्य से कम (पाटित) प्रतिशत में	11.84%	11.05%
ख	एन आई पी से कम मात्रा (क्षति) प्रतिशत में	7.27%	9.11%
ग	भारतीय कीमत से कम मात्रा प्रतिशत में	9.25%	10.46%

89. जापान और रूस से तीसरे देशों को कुल निर्यातों में से निर्यात का विश्लेषण निम्नलिखित को दर्शाता है :

- सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात भारतीय खपत का 11.84 प्रतिशत (रूस) और 11.05 प्रतिशत (जापान) है।
- घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम कीमत पर निर्यात भारतीय मांग का 7.27 प्रतिशत (रूस) और 9.11 प्रतिशत (जापान) था।
- भारतीय कीमत से कम कीमत पर निर्यात भारतीय मांग का 9.25 प्रतिशत (रूस) और 10.46 प्रतिशत (जापान) था।

अ. 3.4 जांच की अवधि के बाद की अवधि का विश्लेषण

90. प्राधिकारी ने पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना का निर्धारण करने के उद्देश्य से जांच की अवधि के बाद की अवधि (अप्रैल 2020 से अगस्त 2020) के लिए भी विश्लेषण किया है। यह देखा जाता है कि दोनों संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में जांच की अवधि के बाद की अवधि में तेजी से वृद्धि हुई है जो यह दर्शाता है कि यदि शुल्क को समाप्त होने दिया जाये तब आयातों में और अधिक वृद्धि की संभावना है। इसके अलावा प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी स्थिति में जांच की अवधि की बाद की अवधि में कार्य निष्पादन संभवतः कोविड महामारी के कारण भारत में राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन के कारण प्रतिनिधिक नहीं होना है।

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	जांच की अवधि	जांच की अवधि के बाद की अवधि (वार्षिकीकृत)
1	संबद्ध आयात	5,866	10,037	11,171	5,732	17,841
2	जापान	350	-	-	300	3,888
3	रूस	5,516	10,037	11,171	5,432	13,953

91. यह देखा जाता है कि दोनों संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में जांच की अवधि के बाद की अवधि में तेजी से वृद्धि हुई है जो यह दर्शाता है कि आयातों में और अधिक वृद्धि की संभावना है।

अ. 3.5 यदि शुल्कों का समय आगे नहीं बढ़ाया जाता है तब घरेलू उद्योग का संभावित कार्य निष्पादन

92. आवेदक ने यह दावा किया है कि यदि यह आयातों के अनुरूप अपनी बिक्री कीमत निर्धारित करने के लिए बाध्य होना पड़ता, तब इसे बहुत अधिक हानि हुई होती। प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग की लागत की तुलना की है। यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की लागत से कम है। यदि संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हो, तब घरेलू उद्योग इन आयातों के अनुरूप अपनी कीमतों को निर्धारित करने के लिए बाध्य होगा, जिसके फलस्वरूप हानि होगी।

ट. प्रकटन पश्चात अनुरोध

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध पुनरावृत्ति प्रकृति के हैं और हितबद्ध पक्षकारों ने अधिकांशतः अपने पूर्व के अनुरोधों को दोहराया है जिसकी पहले ही जांच और उसका निवारण प्राधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रकटन विवरण के संबंध में किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

ट.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

94. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. प्रपत्र ख, घ, में अनुमति दी गई/अनुमति न दी गई खर्च, उपयोग की गई आदर्शतम क्षमता उपयोग और लगाई गई पूंजी सहित क्षति रहित कीमत के पूर्ण विवरण से संबंधित ब्यौरा दिए जाने का अनुरोध किया जाता है। यद्यपि, क्षति रहित कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर किया गया है, परिकलन नहीं दिए गए हैं और घरेलू उद्योग निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत पर टिप्पणी देने में सक्षम नहीं है।
- ii. प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन की गणना करने में भाड़े पर ध्यान नहीं दिया है।
- iii. शुल्क की वही मात्रा दी जा सकती है क्योंकि वर्तमान शुल्क से सतत पाटित आयातों के विरुद्ध घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने का उद्देश्य पूरा हो रहा है।
- iv. रोसप्लास्ट ओओओ एलएलसी, रूस ने मूल जांच में भाग लिया और वर्तमान जांच का उत्तर नहीं दिया है। शुल्क की सिफारिश करते समय इसे नोट किया जा सकता है।
- v. सितंबर, 2020 में संबद्ध देशों से आयात समान वृद्धि को दर्शाते हैं।
- vi. संबद्ध देशों से पाटन तब भी जारी रहा है जब शुल्क लागू हैं जो यह दर्शाता है कि उत्पादक शुल्कों के न होने की स्थिति में संभवतः पाटन को जारी रखेंगे अथवा और अधिक मात्रा में भी करेंगे।
- vii. इसके अलावा, सकारात्मक कीमत कटौती इस बात की पुष्टि करती है कि यह लागू पाटनरोधी शुल्क है जिसमें घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने से आयातों को रोका है।
- viii. दोनों संबद्ध देशों से कम कीमत पर सकारात्मक विक्री अथवा क्षति मार्जिन यह दर्शाता है कि ये आयात घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारक हैं।
- ix. पाकिस्तानी नेशनल टैरिफ कमीशन ने रूस से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी जांच की शुरुआत की है। यह निर्यातानुसूचीकरण और रूस के उत्पादकों द्वारा तीसरे देश से पाटन को उजागर करता है। यदि ये शुल्क पाकिस्तान द्वारा लगाए जाते हैं तब इसके फलस्वरूप उनके लिए एक अन्य बाजार बंद हो जाएगा।
- x. कच्चे माल की कीमतों के प्रति तैयार वस्तुओं की कीमत के अनुपात को देखते हुए, औसत विश्व-स्तर की तुलना में संबद्ध देशों के लिए यह कमतर है। जापान और रूस में उत्पादक अपने निर्यात बाजार को बनाए रखने के उद्देश्य से बाजार कीमतों की तुलना में अपनी कीमतों को कमतर रख रहे हैं।
- xi. प्रयोक्ता और संघ ने केवल वक्तव्य दिए हैं और वे शुल्कों के प्रतिकूल प्रभावों की मात्रा बताने में सक्षम नहीं हुए हैं। उपभोक्ताओं पर शुल्क के प्रतिकूल प्रभाव को सिद्ध करने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है।
- xii. संबद्ध वस्तुओं की खपत में पिछले एक दशक में बहुत अधिक सुधार हुआ है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इन शुल्कों का प्रयोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
- xiii. तिरूमलाई केमिकल्स और आईजी पेट्रोकेमिकल्स के नए संयंत्रों में वाणिज्यिक उत्पादन शीघ्र शुरू होने की आशा है। विस्तार के बाद क्षमता भारत में अनुमानित मांग की तुलना में बहुत अधिक होगी।

- xiv. केएलजे प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड 2 लाख मीटन. का नया संयंत्र स्थापित कर रहा है। भारत में क्षमताएं 7 लाख मीटन. के दायरे में होने की आशा है जो भारत में संभावित मांग से अधिक होगी।
- xv. मांग-आपूर्ति में अंतर नहीं होने और आयातों पर निर्भरता नहीं होने के साथ, इंडियन फ्थेलिक एनहाइड्राइड इंडस्ट्री पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर उद्योग बन जाएगा।
- xvi. विगत जांचों में यह बार-बार पाया गया है कि व्यापार शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।
- xvii. महानिदेशालय रक्षोपाय ने जनहित में रक्षोपाय शुल्क(जो उचित कीमत पर किए गए आयातों के विरुद्ध है) पाया। वर्तमान मामले में, यह मुद्दा इस उत्पाद का अनुचित पाटन है।
- xviii. वित्त मंत्रालय ने हाल में प्राधिकारी द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद कोरिया गणराज्य से फैटेलिक एनहाइड्राइड के आयातों पर द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क लगाया है। प्राधिकारी ने पहले ही यह पाया था कि शुल्कों को लगाना जनहित के विरुद्ध नहीं था।
- xix. पाटनरोधी शुल्क अन्य देशों में उत्पादकों द्वारा अनुचित कीमत भेदभाव का निवारण है जो भारत के उद्योग के लिए क्षतिकारक है। यह अनुचित कीमत निर्धारण का समाधान करने के उपाय के बजाए उद्योग को संरक्षण नहीं है।
- xx. भारत में तीन उत्पादक हैं और आयात अनेक स्रोतों से हो रहे हैं और बाजार में एक अन्य नई कंपनी आने जा रही है। इनके बीच बहुत अधिक परस्पर प्रतिस्पर्धा है और घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों पर नियंत्रण रखना होगा।
- xxi. जनहित अपने आप को केवल उपभोक्ता उद्योग तक सीमित नहीं रखता है और वास्तव में यह बहुत व्यापक शब्द है जिसमें इसके दायरे में घरेलू उद्योग भी शामिल है।
- xxii. मैसर्स थिरूमलाई केमिकल्स लिमिटेड और मै. आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने नए संयंत्रों के लिए पहले ही लगभग 135 करोड़ रु. और 345 करोड़ रु. का निवेश किया है। इसके अलावा, मै. थिरूमलाई केमिकल्स लिमिटेड संबद्ध वस्तुओं के नए ग्रीनफील्ड परियोजना के वास्ते लगभग 450 करोड़ रु. का निवेश कर रहा है। ऐसे अत्यधिक निवेश किए जाने के साथ यह आवश्यक है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा अनुसरण की जा रही अनुचित व्यापार कार्यपद्धतियों को रोकने के लिए उपयुक्त शुल्क लगाया जाए।
- xxiii. भारत सरकार मेक इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांत को आगे बढ़ा रही है लेकिन भारतीय फ्थेलिक एनहाइड्राइड उद्योग आयातों पर बहुत अधिक निर्भर हो रहे हैं।
- xxiv. यह देखा जाएगा कि आयातों के प्रति निर्यात का अनुपात इन वर्षों के दौरान उस सीमा तक कम हुआ है कि जबकि निर्यात आयातों से पहले बहुत अधिक थे, ये आयात अब निर्यात की तुलना में बहुत अधिक हैं, आयात के प्रति निर्यात के अनुपात में 2001-02 में 3.93 से वर्ष 2019-20 में 0.17 तक गिरावट आई है।

ट.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

95. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में सामान्य मूल्य के आधार को प्रकट नहीं किया है जो नियम 16 का उल्लंघन करता है।
- ii. वर्तमान मामले में क्षति के संबंध में लिया गया रुख कोरिया गणराज्य के विरुद्ध रक्षोपाय मामले में निष्कर्ष के प्रतिकूल है।
- iii. यह टिप्पणी कि कम कीमत पर बिक्री दोनों संबद्ध देशों से सकारात्मक है, का वर्तमान मामले में कोई अर्थ नहीं है क्योंकि संबद्ध आयात के कारण कोई क्षति नहीं हुई।
- iv. क्षति मार्जिन क्षति का कोई मानदंड नहीं है, जैसाकि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है।

- v. प्रकटन विवरण इस तथ्य को हानि पहुंचाता है कि संबद्ध देशों से क्षति की समग्र अवधि के दौरान आयात भारतीय मांग की तुलना में बहुत कम थे और ऐसे आयातों पर शुल्कों को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।
- vi. जांच की अवधि के बाद की अवधि में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन के संबंध में संघ के अनुरोध का समाधान प्राधिकारी द्वारा प्रकटन विवरण में नहीं किया गया है।
- vii. यदि प्राधिकारी जांच की अवधि के बाद की अवधि की जांच करते हैं तब ये पाटन और क्षति से संबंधित मानदंडों, दोनों के लिए जांच कर सकते हैं और जांच को केवल आयातों की मात्रा तक सीमित नहीं रखना चाहिए जो एक स्वतंत्र मानदंड के रूप में कुछ भी नहीं का द्योतक है।
- viii. प्रकटन विवरण में विश्वास की गई संभावना संबंधी सूचना असमर्थित साक्ष्य पर आधारित है और प्राधिकारी ने ऐसे आंकड़ों की सत्यता की जांच नहीं की है। सारांश आंकड़े आवश्यक तथ्यों के प्रकटन की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं।
- ix. यदि संबद्ध देश अप्रयुक्त क्षमताओं और तीसरे देश के पाटन का स्रोत था, जैसाकि प्रकटन विवरण में अनुमान लगाया गया है, ऐसे देशों से आयातों का हिस्सा बहुत अधिक हुआ होता।
- x. तीसरे देश की कीमतों का आधार संबद्ध देशों से तीसरे देश के निर्यातों की जांच के लिए नहीं दिया गया है जो एनआईपी और सामान्य मूल्य से अधिक और कम हैं।
- xi. केएलजे प्लास्टिक्साइजर्स लिमिटेड की योजना 100केटी संयंत्र की है और हमें 200केटी के लिए क्षमता विस्तार के साक्ष्य के बारे में जानकारी नहीं है। ये क्षमताएं अगले तीन और वर्षों में चालू हो सकती हैं और प्राधिकारी के लिए संबद्ध देशों से संबद्ध आवश्यक आयातों पर शुल्क लगाना तब तक अनुचित है जब तक ऐसी सभी क्षमताएं लागू हो सकती हैं।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

96. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध पुनरावृत्ति प्रकृति के हैं। इन अनुरोधों की पहले ही जांच इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर की गई है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अतिरिक्त/नए संगत अनुरोधों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की है:
97. घरेलू उद्योग का दायरा कोरिया से आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच तथा वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में अलग-अलग है। मैसर्स एसआई ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच में घरेलू उद्योग के दायरे के भीतर नहीं था। इस कारण से, दोनों जांचों में घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंडों की तुलना सीधे नहीं की जा सकती है।
98. जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों पर विचार किए जाने पर दोनों हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के बाद की अवधि में कोविड-19 महामारी की अवधि और उससे जुड़े लॉकडाउन की अवधि शामिल होगी और इस कारण से यह शुल्कों को या तो वापस लेने अथवा उसका समय विस्तार करने की आवश्यकता को निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं कर सकता है। घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन और भारत में आयात दोनों कोविड महामारी के कारण भारत में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुआ था।
99. इस अनुरोध के संबंध में कि संबद्ध देशों से आयात कभी भी आयातों का प्रमुख स्रोत नहीं था, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल जांच में संबद्ध देशों से आयात इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम सीमा के अधिक था।
100. तीसरे देश के निर्यात आंकड़े तथा संभावना संबंधी सूचना के स्रोत के संबंध में उठाए गए मुद्दे के बारे में यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से विदेशी उत्पादकों द्वारा भाग नहीं लेने की स्थिति में और किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से ऐसे किसी सत्यापन योग्य आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों

पर विश्वास किया है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और आवेदकों द्वारा दिए गए सीमा शुल्क संबंधी आंकड़ों पर विचार किया है।

101. क्षमता विस्तार के संबंध में किए गए अनुरोध पर यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने 200केटी की क्षमता विस्तार दर्शाते हुए, दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। इस संघ ने यह तर्क दिया है कि क्षमता विस्तार 100केटी का होगा और उसे पूरा करने में 3 वर्ष लगेंगे। यह नोट किया जाता है कि दो मौजूदा उत्पादकों ने पहले ही अपनी क्षमता का विस्तार किया है और विस्तारित क्षमता के संबंध में वाणिज्यिक उत्पादन शीघ्र शुरू होने जा रहा है। यदि केएलजे प्लास्टिसाइजर्स की योजनाबद्ध क्षमता विस्तार 100केटी के रूप में भी माना जाता है तब यह देखा जाता है कि घरेलू उत्पादक भारत में इस उत्पाद की पूर्ण मांग पूरा करने में सक्षम होंगे। किसी भी स्थिति में प्रयोक्ता उचित कीमत पर संबद्ध वस्तुओं का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।
102. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति रहित कीमत का परिकलन और उसके प्रकटन के संबंध में किए गए अनुरोध पर, यह नोट किया जाता है कि क्षति रहित कीमत का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध-III के अनुसार किया गया है। एनआईपी इस संबंध में अनुसरण की जा रही कार्य-पद्धति के अनुरूप घरेलू उद्योग को प्रकट किया गया।
103. क्षति के लिए मानदंडों की जांच के संबंध में अनुरोध पर, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने अपनी सतत् कार्य-पद्धति के अनुसार क्षति के सभी मानदंडों की जांच की है।
104. सामान्य मूल्य प्रकट न किए जाने के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि विदेशी उत्पादकों ने वर्तमान जांच में प्राधिकारी को सहयोग नहीं किया है और इस कारण से प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विवश थे। इसके अलावा, निर्धारित सामान्य मूल्य में आवेदक घरेलू उद्योग की गोपनीय सूचना शामिल है। इस कारण से, सामान्य मूल्य के प्रकटन के फलस्वरूप आवेदक घरेलू उद्योग की गोपनीय सूचना का प्रकटन हुआ होता।
105. यह देखा जाता है कि क्षति की समग्र अवधि के दौरान जापान से आयातों के तीन आयात लेन-देन हुए थे। क्षति की अवधि के दौरान जापान से विचाराधीन उत्पाद का आयात क्षति की अवधि के दौरान 5,08,797 मी.टन के आयात और 14,96,364 मी.टन की भारतीय मांग में बहुत कम अर्थात् 650 मी.टन था। क्षमता की तुलना में विचाराधीन उत्पाद की खपत जापान के मामले में बहुत अधिक है और इस प्रकार यह बहुत अधिक घरेलू खपत को दर्शाता है। यह नोट किया जाता है कि जापान के उत्पादक की मौजूदा क्षमता उपयोग भी बहुत अधिक हद तक है। जबकि क्षति की अवधि के दौरान जापान के उत्पादक का औसत क्षमता उपयोग 86-92 प्रतिशत था, इस अवधि के दौरान रूस के उत्पादकों का औसत क्षमता उपयोग 60-65 प्रतिशत था। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जापान के उत्पादक काफी हद तक अपनी क्षमताओं का उपयोग कर रहे हैं और बहुत अधिक घरेलू खपत कर रहे हैं। इसके विपरीत, रूस के उत्पादकों का मौजूदा क्षमता उपयोग बहुत कम है और क्षमता के प्रतिशत के रूप में खपत भी जापान के विपरीत रूस में बहुत कम है। इस कारण से, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जबकि जापान से आयातों में अत्यधिक वृद्धि की कोई संभावना नहीं है, बहुत अधिक अप्रयुक्त क्षमता के कारण पाटनरोधी शुल्क के समाप्त किए जाने की स्थिति में रूस से आयातों में बहुत अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

ठ. भारतीय उद्योग के हित

106. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के द्वारा हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने से संबद्ध देश/प्रक्षेत्र से किसी भी प्रकार से आयात पर रोक नहीं लगेगी और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
107. यह नोट किया जाता है कि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्क के कारण कमी नहीं आएगी, विशेषकर यदि पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक राशि तक

सीमित हो। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाने से पाटन कार्यपद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जाएगा, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट रुक जाएगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

ड. निष्कर्ष

108. दिए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किए गए अनुरोधों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों जिसे उपर्युक्त जांच परिणामों में रिकॉर्ड किया गया है, के संबंध में तथा घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा उसके फिर से होने की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

- क. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का सतत पाटन हुआ है।
- ख. घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- ग. क्षति की अवधि के दौरान आयातों की मात्रा, जापान में घरेलू खपत, इस अवधि के दौरान जापान के उत्पादकों का क्षमता उपयोग जैसे कारक उस स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की किसी संभावना को नहीं दर्शाते हैं जब जापान से आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने के अनुमति दी जाती है।
- घ. कीमत में सकारात्मक कटौती, मांग की तुलना में अधिक उत्पादन, रूस में निष्क्रिय उत्पादन क्षमताएं, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता, तीसरे देश में पाटन जैसे कारक उस स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना को दर्शाते हैं जब रूस से आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की अनुमति दी जाती है।
- ड. देश में अत्यधिक क्षमता विस्तार जैसे कारक जो मांग-आपूर्ति में अंतर, भारतीय उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा समाप्त करेगा, जैसे कारक यह दर्शाते हैं कि डाउनस्ट्रीम उद्योग अथवा उपभोक्ताओं पर शुल्क का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

ढ. सिफारिशें

109. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रयाप्त अवसर दिया गया था ताकि वे पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध करा सकें।
110. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि यदि रूस से आयातों के विरुद्ध मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने की अनुमति दी जाती है तब घरेलू उद्योग को पाटन और परिणामी क्षति की संभावना है, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखना रूस से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर अपेक्षित है। हालांकि जापान से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।
111. इन परिस्थितियों में, प्राधिकारी इसे उपयुक्त मानते हैं कि रूस से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा मात्रा जारी रखने की सिफारिश की जाए। इस प्रकार, प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं कि रूस से शुल्क तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए रखने की सिफारिश की जाए।

शुल्क तालिका

क्र.स	शीर्ष/ उपशीर्ष	संबद्ध वस्तुओं का विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29173500	फथेलिक एनहाइड्राइड	रूस	रूस सहित कोई देश	कोई भी	159.43	मी.टन	यूएसडॉ.

2	29173500	फथेलिक एनहाइड्राइड	रूस को छोड़कर अन्य कोई देश	रूस	कोई भी	159.43	मी.टन	यूएसडा.
---	----------	-----------------------	----------------------------------	-----	--------	--------	-------	---------

ण. आगे की प्रक्रिया

112. केन्द्र सरकार के इस आदेश, जो इस सिफारिश के कारण हो सकता है, के विरुद्ध अपील इस अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष होगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

FINAL FINDINGS

New Delhi, the 5th January, 2021

Case No. ADD-SSR-07/2020

Subject : Sunset Review of anti-dumping investigation concerning imports of "Phthalic Anhydride" originating in or exported from Japan and Russia.

F. No. 7/11/2020 – DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Act'), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the 'Rules' or 'AD Rules') thereof;

A Background of the case

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) initiated an antidumping investigation in respect of imports of "Phthalic Anhydride" (hereinafter also referred to as "PAN" or the "subject goods" or "PUC" or "Product Under Consideration") originating in or exported from Japan and Russia on 9th May 2014 and after conducting the investigation recommended imposition of definitive duty vide Final Findings Notification No. 14/6/2014-DGAD dated 3rd November, 2015. On the basis of recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No. 56/2015-Customs (ADD) dated 4th December 2015.
2. Section 9A (5) of the Act, inter alia, provides that anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the above, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
3. Rule 23(1B) of the Rules provides as follows:

"...any definitive anti-dumping duty levied under the Act shall be effective for a period not exceeding five years from the date of its imposition, unless the Designated Authority comes to a conclusion, on a review initiated before that period on its own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the expiry of that period, that the expiry of the said anti-dumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry."

4. M/s IG Petrochemicals Limited, M/s Thirumalai Chemicals Limited and M/s SI Group India Private Limited (hereinafter referred to as "applicants" or "domestic industry") filed a duly substantiated application on behalf of the domestic industry, in accordance with the Act and the Rules alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or exported from subject countries and consequent injury to the domestic industry and have requested for review and continuation of the anti-dumping duties, applicable on the imports of the subject goods, originating in or exported from Russia and Japan.
5. Based on the application filed on behalf of the domestic industry in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules with prima facie evidence of likelihood of dumping and injury, the Authority initiated the sunset review investigation vide Notification No. F. No. 7/11/2020-DGTR (SSR No. 07/2020) dated 11th May, 2020 to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry and whether there is a need for continued imposition of antidumping duty in respect of the subject goods originating in or exported from Russia and Japan .
6. The scope of the present review covers all aspects of the previous investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

B Procedure

7. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
 - i. The Authority notified the embassy of the subject countries in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule 5(5) of the AD Rules.
 - ii. The Authority issued a Notification dated 11th May, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
 - iii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Embassy of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 60 days of the initiation notification in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules.
 - iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters, known importers and to the embassy of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules.
 - v. The Embassy of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
 - vi. The Authority sent exporter's questionnaire to the following known producers/ exporters in the subject countries, whose details were made available by the applicants, to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. Gazprom Neftekhim Salavat, Russia
 - b. JSC Ural Chemical Co, Russia
 - c. West-Siberian Steel, Russia
 - d. Angarsk Petrochemical, Russia
 - e. Polymer Pack Go, Russia
 - f. Uralkhimprom Podlesnaya, Russia
 - g. Rosplast Ooo LLC, Russia
 - h. OJSC Kamtex-Himprom, Russia

- i. JFE chemical corporation, Japan
- j. New japan chemical Co. Limited, Japan
- k. Nippon Shokubai, Japan
- l. C-Ghem Co., Limited, Japan
- vii. None of the producers/exporters from the subject countries have filed exporter's questionnaire response.
- viii. The Authority forwarded a copy of the Initiation Notification to the following known importers/users/user associations, whose names and addresses were made available to the authority, of subject goods in India and advised them to make their views known in writing within the time limit prescribed by the Authority in accordance with the Rule 6(4):
 - a. M/s KLJ Plasticizers Limited
 - b. M/s Mazda Colors Limited
 - c. M/s Pck Oil & Solvents Limited
 - d. M/s Lona Industries Limited
 - e. M/s Silvassa Plast Private Limited
 - f. M/s Aarti Industries Limited
 - g. M/s Mechemco Industries Private Limited
 - h. M/s Rachna Plasticizers
 - i. M/s Micro Inks Limited
 - j. M/s Phthalo Colors & Chemicals (I) Limited
 - k. M/s Heubach Colour Private Limited
 - l. M/s Ramniklal S. Gosala & Co.
 - m. M/s Sanman Trade Impex Private Limited
 - n. M/s Pertochem Middle East (India) Private Limited
 - o. M/s A-One Chem Trade Private Limited
 - p. M/s Amjey Chemicals Trade Private Limited
 - q. M/s Sanjay Chemicals (India) Private Limited
 - r. M/s Hazel Mercantile Limited
 - s. M/s Indian Plastics Federation
 - t. M/s Indian Plasticizers Manufacturers Association
 - u. M/s Indian Paint Association
 - v. M/s Chemical Industries Association
 - w. M/s Indian Chemical Council
- ix. The following importers or consumers of the product have filed the importer's questionnaire response in the prescribed format:
 - a. M/s KLJ Plasticizers Limited
 - b. M/s Payal Polyplast Private Limited
- x. M/s Indian Plasticizers Manufacturers Association (IPMA) and Government of Russia filed letters of participation in response to the initiation notification. The Government of Japan filed written submission as well.

- xi. Exporters, foreigner producers and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- xii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xiii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by all interested parties. A list of all interested parties was uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to ongoing global pandemic.
- xiv. The period of investigation for the purpose of the present investigation has been considered from April, 2019 to March, 2020 (POI). The injury investigation period has been considered as the period from April 2016 to March 2017, April 2017 to March 2018 and April 2018 to March 2019 and POI. The Authority has also considered April 2020 to August 2020 as the post - POI for the purpose of examining likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
- xv. Additional/supplementary information was sought from the applicants and other interested parties to the extent deemed necessary. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the investigation.
- xvi. The Non-injurious Price (NIP) is based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules. It has been worked out so as to ascertain whether duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xvii. Information obtained from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) on transaction-wise import data for the past three years, and the period of investigation has been adopted for determination of volume and value of imports of product concerned in India.
- xviii. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to all interested parties to present their views orally in the oral hearing held on 11th November, 2020, which was attended by various parties. The oral hearing was held through video conferencing in view of the special circumstances arising out of the COVID- 19 pandemic. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of these views, in order to enable opposing interested parties to file rejoinders thereafter.
- xix. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in these final findings.
- xx. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded these final findings on the basis of the facts available.
- xxi. In accordance with Rule 16 of the Rules, the essential facts of the investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 18th December, 2020 and comments received thereon, considered relevant by the Authority, have been addressed in these final findings. The Authority notes that most of the post disclosure submissions made by the interested parties are mere reiteration of their earlier submissions. However, the post disclosure submissions to the extent considered relevant are being examined in these Final Findings.

- xxii. *** in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxiii. The exchange rate adopted by the Authority during the POI for the subject investigations is 1 US\$= Rs. 71.65

C Product under consideration

8. The product under consideration in the present investigation is "Phthalic Anhydride" (PAN). Phthalic Anhydride (PAN) is an anhydride of Phthalic Acid and is commercially produced by catalytic oxidation of Ortho-xylene or Naphthalene. It is a colourless solid, variously referred as Phthalic Anhydride flakes, Phthalic Anhydride (98% min.), Phthalic Acid Anhydrous, Phthalic Anhydride (99.8% min), etc. Specifications of Phthalic Anhydride includes its physical appearance, colour of solid flakes, colour of molten product, solidification point, Phthalic Anhydride content by weight, other anhydrides & organic impurities' content by weight and acidity index.

C.1 Submissions of the domestic industry

9. The domestic industry has submitted as follows with regard to product under consideration and like article:
- Product under consideration in the present petition is 'Phthalic Anhydride', the principal commercial form of Phthalic Acid
 - Since the present investigation is a sunset review investigation, the scope of product under consideration remains the same as in the original investigation.
 - The domestic industry is producing a like article to product under consideration.

C.2 Submissions of other interested parties

10. Other interested parties have not made any submissions with regard to product under consideration and like article.

C.3 Examination by Authority

11. The product under consideration in the original investigation as well as in the present sunset review is Phthalic Anhydride. In the previous investigation, the product under consideration was defined as under. The Authority has considered the same scope of the product under consideration for the present purposes:

The product under consideration in the present investigation is "Phthalic Anhydride". Phthalic Anhydride, also referred as PAN or PA, is an anhydride of Phthalic Acid, and is commercially produced by catalytic oxidation of Ortho-xylene or Naphthalene. It is a colourless solid, variously referred as Phthalic Anhydride flakes, Phthalic Anhydride (98% min.), Phthalic Acid Anhydrous, Phthalic Anhydride (99.8% min), etc. The product is produced only in one grade. As regards different applications, it does not have distinguishable different types of forms. It is mainly used in the production of phthalate esters, which functions as plasticizers. It is an important chemical intermediate in plastic industry. It is also used in making of the products like Polyester Resins, Alkyd Resins used in paints and lacquers, Unsaturated Polyester Resins, Polyester Polyols, Dyes and Pigments, Halogenated Anhydrides, Polyetherimide Resins, Isatonic Anhydride, Insect Repellents etc.

Phthalic Anhydride is an organic chemical classified under customs sub-heading No. 29173500 under the Custom Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

12. The subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. In view of the same, the product under consideration produced by the domestic industry is treated as like article to the product under consideration imported from subject countries.

D Domestic industry and standing

13. Rule 2(b) of the AD rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term, 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers."

D.1 Submissions of domestic industry

14. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of the domestic industry:

- i. All the three producers in India are participating in the investigation.
- ii. Applicants have not imported the subject goods and are not related, either directly or indirectly, to any exporter in the subject countries or any importer of the dumped article within the meaning of Rule 2(b).
- iii. The application satisfies the requirement of the rules.

D.2 Submissions of other interested parties

15. The other interested parties have not made any submissions with regard to domestic industry and its standing.

D.3 Examination by the Authority

16. The present application has been filed by M/s IG Petrochemicals Limited, M/s Thirumalai Chemicals Limited and M/s SI Group India Private Limited. There is no other existing producer in India. Therefore, the applicants account for entire production in India. These applicants have provided relevant information as per the prescribed format and the applicants are eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules. The application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules, even though standing within the meaning of Rule 5(3) is not required to be established in a sunset review initiated under Rule 23.

E Miscellaneous submission**E.1 Submissions of domestic industry**

17. Following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- i. Profits of the domestic industry have dried up and the industry has suffered from extremely poor returns. Allegation of high price charged by the domestic industry should be completely ignored.
- ii. Demand and supply gap cannot justify dumping.
- iii. KLJ Plasticizers Limited is in the process of installing PAN plant with capacity around 200 KT. These capacities will become operational by 2024 tentatively. The capacity after the expansions will be much more than the projected demand in India.
- iv. Extension of duties will not prevent imports. Imports can continue to happen from subject countries as well as other countries. Even the domestic industry would have to compete which will keep domestic industry's prices in check.
- v. BIS will bring standards. It is improper to consider that it is used to monopolize market and such allegation amounts to levelling serious allegations against Govt. functioning and decision making.
- vi. As regards the application filed by domestic industry with different period of investigations, it is submitted that the application for sunset review as well as fresh investigation are filed with the same period of investigation. Applicants have already stated that domestic industry is suffering injury in the period of investigation due to dumping from fresh countries and there is a likelihood of injury from the subject countries in this sunset review application.

- vii. As regards argument with respect to bilateral safeguard measures on imports from South Korea, it is submitted that in bilateral safeguard case, it is Korean imports which has been identified as the cause of injury. The domestic industry is conscious and well aware that it will not get protected beyond injury margin.
- viii. There need not be one sole reason for the injury to the domestic industry. The authority needs to only assess if there is a "genuine and substantial relationship of cause and effect" of dumping and injury.

As regards the claim of report from TecnonOrbiChem being claimed confidential, it is submitted that report is based on third-party information which the applicants are not permitted to disclose. However, the figures adopted from the report have been disclosed. It is these figures which shall form the basis for determination.
- ix. As regards the claim that the duty will lead to closure of phthalate plasticizer industry, it is submitted that no information on number of users which have shut down plants in past on account of antidumping or safeguard duty has been given by other interested parties.
- x. Consumption of PAN shows healthy growth of downstream industry even when antidumping duty or safeguard duty were in force. Duties were imposed after due examination of public interest.

E.2 Submissions of other interested parties

- 18. Other interested parties have made following miscellaneous submissions.
 - i. There is a demand and supply gap.
 - ii. The Indian producers charge high prices by misusing trade remedial measures.
 - iii. PAN manufacturers are blocking imports of Phthalic Anhydride by anti-dumping duty, safeguard duty or pushing for BIS specifications so that they can monopolize the market.
 - iv. Applicants are presenting different period of investigation and conflicting cause of injury before the Authority in different investigations.
 - v. To support claims of excess capacities, a report from TecnonOrbiChem has been used but is held confidential.
 - vi. Continuation of anti-dumping duty will open flood gates for imports of Phthalate Plasticizers which is also being imported with zero basic custom duty.
 - vii. Value addition in converting Phthalic Anhydride into phthalate plasticizers is very low and with low value addition, increase in raw material price will make it difficult to compete with imported phthalate plasticizer.
 - viii. Anti-dumping duty will lead to closure of phthalate plasticizer industry down the line and leading to loss of employment.
 - ix. Government of India has revoked antidumping duties applicable on imports of PTA and Acrylic Fibre which are key inputs for various sectors. Same should be done in the present case as well.
 - x. PAN being a key input for many units employing thousands of people, it is essential that such input is made available to units at fair prices and at required volume.
 - xi. Authority must take affidavit from producers on factual position of capacity expansions since such claims have been made in many recent investigations but the expansions are never complete.

E.3 Examination by the Authority

- 19. The Authority made non-confidential version of the information provided by various interested parties available to all interested parties for inspection through the public file containing non-confidential version of evidence submitted by various interested parties.
- 20. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality, to the extent considered relevant, were examined by the Authority and addressed

accordingly. The Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was duly examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

21. The Authority notes that the demand supply gap in the country does not bar a domestic industry from seeking redressal from dumped imports. Demand-supply gap does not justify dumping. The information on record shows that the domestic industry is undergoing capacity expansion. In fact, the domestic industry has enhanced capacity and has made investment towards the same. Further, documentary evidence has been provided showing that KLJ Plasticizers Limited is in the process of setting up capacity of around 200 KT. The domestic industry contended that considering the capacity expansions undertaken, the capacity of the domestic industry will be significantly higher than the demand in country. The foreign producers can always meet the Indian demand by selling the product at undumped prices. Even after the imposition of antidumping duty, the imports are not restricted in the country. Therefore, there is no basis for the claim that imposition of ADD can lead to shortage of the raw material for the downstream industry. The Authority notes that imposition of anti-dumping duty provides level playing field and does not prevent fair competition in the market. The Authority also notes the submission of the domestic industry that subject goods is produced and exported by many countries. The users are free to import the subject goods from any source.
22. The Authority notes that the trade remedial measures have been imposed in past on the imports of the subject goods from various sources. These measures are invoked after following a quasi-judicial investigation with participation of all interested parties, and after due examination of merits, and in due compliance with the law and examination of the public interest. The applicant has given evidence of likelihood of increase in imports of the subject goods from the subject countries. Contrarily, the other interested parties have not provided any justification/evidence for the claim of likelihood of increase in imports of downstream product. Therefore, there is no reason to believe that the present continuation of anti-dumping will lead to an increase in imports of the downstream industry.

F Determination of NORMAL value, export price and dumping margin

F.1 Normal Value

23. Under Section 9A (1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:
 - i. *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting countries or territory as determined in accordance both the rules made under sub-section (6); or*
 - ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting countries or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting countries or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*
 - a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting countries or territory or an appropriate third countries as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - b. *the cost of production of the said article in the countries of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

F.2 Submissions of domestic industry

24. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows: -
- i. Evidence of prices of subject goods in the domestic market of Russia and Japan or the price lists of the producers is not available in public domain.
 - ii. Exports from Russia to Poland have highest share in the exports from Russia. Similarly, exports from Japan to Malaysia have highest share in the exports from Japan. Exports prices from the subject countries to these two countries can be considered appropriate for determination of normal value.
 - iii. Export price can be calculated after due adjustments in the DGCI&S transaction wise data for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses and inland freight expenses.
 - iv. Dumping margin determined on the basis of above is not only positive but is significant.
 - v. Even if normal value is constructed, the resulting dumping margin is significant.
 - vi. Since none of the producers from the subject countries have participated, the claims of dumping margin are undisputed.
 - vii. Positive dumping even when duties are imposed shows likelihood of dumping when duties will expire.
 - viii. As regards submission that normal value proposed does not justify facts, it is submitted that user association was free to provide relevant information, rather than merely drawing conclusions.
 - ix. As regards submission regarding appropriate surrogate country, the association is under belief that there is a need to identify surrogate country even in case of market economy countries. The requirement is “comparable representative price” of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country.

F.3 Submissions of other interested parties

25. The submissions made by the other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows: -
- i. No justification has been given for considering export price from Russia to Poland as normal value.
 - ii. Source of information for adjustment claimed to arrive at normal value has not been provided.
 - iii. Proposal of domestic industry for determination of normal value should not be accepted since proposed methodology is not justified.
 - iv. Poland and Malaysia cannot be treated as surrogate countries for India.

F.4 Examination by Authority

26. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject countries, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. None of the producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses.

F.4.1 Normal Value determination**Russia**

27. The Authority notes that none of the producers/exporters from Russia have filed exporter's questionnaire response. Since the applicants have not provided any detailed justification for considering Poland as an appropriate third country, the same has not been considered for determining

the normal value. The Authority has thus determined normal value on the basis of facts available in terms of Rule 6(8).

Japan

28. The Authority notes that none of the producers/exporters from Japan have filed exporter's questionnaire response. Since the applicants have not provided any detailed justification for considering Malaysia as an appropriate third country, the same has not been considered for determining the normal value. The Authority has thus determined normal value on the basis of facts available in terms of Rule 6(8).

F.4.2 Export Price

29. Since no response has been received from any producer/exporter from the subject countries, the Authority has determined export price as per "facts available" in terms of Rule 6(8) of the AD Rules in respect Russia and Japan. The export price has been determined on the basis of weighted average import price in India. Since this price is CIF export price, the same has been adjusted on account of ocean freight, insurance, commission, bank charges, port expenses and handling charges, based on facts available, in view of non-cooperation by the producers/exporters concerned.

F.4.3 Calculation of Dumping Margin

30. Considering the normal value and export price determined, as explained above, it is noted that the dumping margin for both Russia and Japan is more than the *de minimis* limit prescribed under the Rules.

S.No.	Particulars	Normal value	Export price	Dumping margin	Dumping margin	Range
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	%
1	Japan	***	***	***	***	20-30%
2	Russia	***	***	***	***	20-30%

G METHODOLOGY FOR INJURY DETERMINATION AND EXAMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK

31. Rule 11 of the Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "*.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
32. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6,7,8,9,10,11,16,18, 19 and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. The Authority in its examination has evaluated the injury parameters which are required under Rule 11 and Annexure II of the Rules and has also examined as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
33. The Authority notes that the application for imposition of antidumping duty has been filed by M/s IG Petrochemicals Limited, M/s Thirumalai Chemicals Limited and M/s SI Group India Private Limited. In terms of Rule 2(b) of the Rules, the Applicants have been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation. Therefore, the cost and injury information of the Applicants, constituting the domestic industry as defined in Rule 2(b), have been examined.

G.1 Submissions of domestic industry

34. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are as under:

- i. Volume of imports from the subject countries have declined over the injury period due to imposition of anti-dumping duty and dumping from other countries.
- ii. Present injury to domestic industry is not due to imports from subject countries.
- iii. Domestic industry is expanding its capacities and once capacity expansion is undertaken, domestic industry will be able to meet entire demand for the product in the country.
- iv. Considering the significant investments planned and made, it is necessary that the Indian market is protected from the unfair trade practice of dumping.
- v. Performance of the domestic industry has deteriorated in respect of parameters such as production, capacity utilization sales, inventories, market share, profits, cash profits and return on investment during the current injury period.
- vi. Domestic industry was faced with idle capacities in the period of investigation despite demand and supply gap.
- vii. Domestic industry suffered decline in sales and faced piling of inventories.
- viii. Faced with significant high inventories and lack of demand domestic industry had to undertake significant exports at distress prices.
- ix. Domestic industry had to compromise not only on its sales opportunities in the domestic market, but also on margins.
- x. Catalyst is changed in every 27-30 months. The year in which it is changed, witnesses high efficiency in plant in terms of production and utilization of raw material and utilities, which subsequently starts declining. Therefore, considering higher production and lower consumption for such a year for determination of NIP will not be appropriate.
- xi. Present deterioration in performance of domestic industry was largely due to dumping from China, Indonesia, Korea RP and Thailand. It nevertheless establishes likelihood of injury to domestic industry from subject imports in the event of cessation of anti-dumping duty.
- xii. Domestic industry is operating with idle capacities, high inventories and was constrained to export significant volumes. There is no reason why it would stop responding to customer queries unless prices expected are abysmally low and unreasonable.
- xiii. Injury margin may be compared by adding freight as consumers decide their purchases and negotiate the prices with the suppliers on the basis of comparison of landed price of imports in their factory warehouse.
- xiv. As regards the submission of the other interested parties that the negative price undercutting shows high price is charged by the domestic industry, the domestic industry submitted that negative price undercutting means domestic industry prices were lower than import prices. Further, had domestic industry charged higher prices, domestic industry profitability would not have been deteriorated and would not have been adverse.
- xv. Applicants have clearly written in application that they are not requesting determination of NIP at customers' level by adding freight. The NIP may be determined at ex-factory level. However, the injury margin should be determined by adding associated freight. Consumers have not disputed the claim of the applicant.
- xvi. As regards the claim of injury due to OX, it is submitted that domestic industry has faced no issues in availability of raw material during period of investigation. It is respondent's own claim that raw material is available at nil custom duty. The domestic industry needs to align its prices to raw material but could not do due to dumped imports.
- xvii. Adverse performance in exports is on account of injury due to dumped imports in country and could be considered as one of factors showing injury to the domestic industry.
- xviii. As regards the claim that domestic industry enjoys advantages, it is submitted that even when domestic industry has these "advantages", its performance is poor which shows vulnerability to dumped imports.

- xix. As regards submission on TCL plant, it is submitted that it is customary to continuously invest in technology and improve efficiency. Statements made in Annual Report are in reference to such technological investments made. Technical performance of TCL in all aspects is on par with other producers globally.

G.2 Submissions of other interested parties

35. The submissions of other interested parties with regard to injury and causal link are as under:

- i. Most of factors of economic parameters of the domestic industry show a positive trend reflecting that the domestic industry is not suffering injury and there is no justification for continuation of hefty duties.
- ii. The performance of the domestic industry has suffered because of the flood of low-priced imports from China PR, Indonesia, Korea RP, Thailand and Taiwan.
- iii. Applicants have admitted that domestic industry did not suffer any continued injury on account of import of subject goods from subject countries.
- iv. Difference in price between Orthoxylene and final product and availability of OX has greatest influence on the performance of PAN manufacturers in India.
- v. Domestic industry is a regular exporter which impacts demand supply situation in India. Manufacturers are selling PAN overseas at a lower price compared to domestic selling price without claiming any kind of injury.
- vi. Proposal to add freight to both NIP and landed price to determine the injury margin is against Annexure III.
- vii. Applicant has presented transaction wise DM/IM by zeroing negative margins, which is not a method adopted by the Authority.
- viii. Major sources of imports are already probed under trade measures. Insignificant imports from subject countries should be freed from anti-dumping duty.
- ix. TCL is operating with a very old plant and technology which causes frequent shutdowns and other issues. Injury is due to such factors.
- x. Producers have other reasons which are influencing their performance but are attributing them to imports in their annual reports in order to take undue advantage of trade remedial measures.
- xi. Domestic industry has a natural advantage on account of nil energy cost and custom duty benefit on imports of raw material. Therefore, they cannot suffer injury.
- xii. PAN manufacturers are not responding to customer inquiries and are quoting arbitrarily high prices.
- xiii. Imports from subject countries constituted barely 1% of Indian demand which shows negligibility of such imports.
- xiv. Imports from Japan are below the threshold limit of 3% across the entire injury period and therefore Japan should be excluded.

G.3 Examination by Authority

36. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. Annexure-II of the Anti-Dumping Rules provides for objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.
37. According to Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act, 1975, anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition, provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time-to-time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of the order of such extension.

38. In consideration of the various submissions made by the interested parties in this regard, the Authority proceeds to examine the current injury, if any, to the domestic industry before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury on account of imports from the subject countries.
39. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters and, thereafter, concludes whether the domestic industry has suffered injury or is likely to suffer injury due to dumping. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and other interested parties.
40. The Authority has taken note of various submissions made by the Domestic Industry and other Interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority in the succeeding paras addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.

G.3.1 Assessment of demand

41. The Authority has determined demand or apparent consumption of the product in India, as the sum of domestic sales of the Indian Producers, and imports from all sources.

S.No.	Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Sales of domestic industry	MT	2,23,200	2,35,591	2,37,924	2,28,046
2	Sales of other producers	MT	24,000	6,000	-	-
3	Imports from subject countries	MT	5,866	10,037	11,171	5,732
4	Imports from other countries	MT	86,184	1,20,402	1,33,488	1,68,723
5	Total demand/consumption	MT	3,39,251	3,72,030	3,82,583	4,02,500

42. It is seen that the demand of the subject goods has continuously increased over the injury period including POI.

G.3.2 Volume effect of dumped imports.

i. Import volume and share of subject countries

43. The effects of the volume of dumped imports from the subject countries as well as imports from other countries have been examined by the Authority.

S.No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Subject Countries	MT	5,866	10,037	11,171	5,732
A	Japan	MT	350	-	-	300
B	Russia	MT	5,516	10,037	11,171	5,432
2	Other countries	MT	86,184	1,20,402	1,33,488	1,68,723
3	Total	MT	92,051	1,30,439	1,44,660	1,74,454
4	Subject countries import in relation to -					
A	Indian production	%	1.98%	3.47%	4.06%	2.13%
B	Demand	%	1.73%	2.70%	2.92%	1.42%
C	Total imports	%	6.37%	7.69%	7.72%	3.29%

44. It is seen that the volume of dumped imports of product under consideration from subject countries increased till 2018-19 but has declined sharply thereafter in the period of investigation.

G.3.3 Price effect of dumped imports.

45. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, the Authority is required to consider the effect of the dumped imports on domestic prices in terms of price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

a. Price Undercutting

46. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. In this regard, a comparison has been made between the landed value of the product from the subject countries and the average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade.

S.No.	Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Net Sales Realisation	Rs/MT	***	***	***	***
2	Subject countries as a whole					
a	Landed Price	Rs/MT	53,098	66,901	73,712	65,562
b	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
c	Price Undercutting	%-Range	20-30%	0-10%	0-10%	0-10%
3	Japan					
a	Landed Price	Rs/MT	51,027	-	-	60,985
b	Price Undercutting	Rs/MT	***	-	-	***
c	Price Undercutting	%-Range	30-40%	-	-	10-20%
4	Russia					
a	Landed Price	Rs/MT	53,230	66,901	73,712	65,815
b	Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
c	Price Undercutting	%-Range	20-30%	0-10%	0-10%	0-10%

47. It is seen that price undercutting is positive in respect of imports from both the countries.

b. Price Suppression/Depression

48. In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority notes the changes in the costs and prices over the injury period.

S.No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Cost of Sales	₹/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>94</i>	<i>117</i>	<i>113</i>
2	Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>119</i>	<i>101</i>

3	Landed Price from subject countries	₹/MT	53,098	66,901	73,712	65,562
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>126</i>	<i>139</i>	<i>123</i>

49. It is seen that both cost of sales of domestic industry and selling price have declined in the period of investigation. However, the decline in selling price is much higher than decline in the cost of sales. The period of investigation has also seen a decline in the landed price of imports. However, considering the insignificant imports made in the period of investigation from the subject countries, the decline in selling price of the domestic industry cannot be attributed to the decline in landed price of imports. Therefore, while the prices of domestic industry are suppressed, they are not due to imports from the subject countries.

c. Price Underselling

50. The price underselling has been evaluated by comparing the non-injurious price with the landed price of the subject imports.

S.No.	Particulars	Non-injurious price (NIP)	Landed price	Price Underselling	Price Underselling	Range of Price Underselling
		RS/MT	RS/MT	RS/MT	%	%
1	Japan	***	60,985	***	***	0-10%
2	Russia	***	65,815	***	***	0-10%

51. It is seen that the price underselling is positive in respect of dumped imports from both the subject countries.

G.3.3 Impact on economic parameters of the domestic industry

52. Annexure - II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity: factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

53. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period.

S.No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Capacity	MT	3,17,110	3,17,110	3,17,110	3,17,110
2	Production	MT	2,72,561	2,83,491	2,75,492	2,69,640
3	Capacity Utilisation	%	86%	89%	87%	85%
4	Domestic sales	%	2,23,200	2,35,591	2,37,924	2,28,046

54. It is noted that –

- a. The capacity of the domestic industry has remained constant throughout the injury period.

- b. The production and capacity utilization of the domestic industry has increased till 2017-18 but declined thereafter.
- c. Domestic sales of the product under consideration has increased till 2018-19 but decreased during the period of investigation.

b. Market share of the domestic industry in demand.

55. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined.

S.No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Domestic industry	%	66%	63%	62%	57%
2	Other Producers	%	7%	2%	0%	0%
3	Subject Countries	%	2%	3%	3%	1%
4	Other Countries	%	25%	32%	35%	42%

56. It is seen that market share of the domestic industry and subject countries has declined over the injury period. Other countries have seen a significant increase in the market share.

c. Inventories

57. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period.

S.No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Average inventory	MT	5,904	3,564	3,429	4,934

58. It is seen that the average inventory level of the domestic industry has shown decreasing trend till 2018-19 and has increased thereafter in the period of investigation.

d. Profit or loss, cash profits and return on investment

59. Performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

S.No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>94</i>	<i>117</i>	<i>113</i>
2	Selling price	₹/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>106</i>	<i>119</i>	<i>101</i>
3	Profit / Loss	₹/MT	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>203</i>	<i>138</i>	<i>4</i>
4	Profit / Loss	₹ Lacs	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>215</i>	<i>147</i>	<i>4</i>
5	Cash profits	₹ Lacs	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>198</i>	<i>143</i>	<i>23</i>
6	Profit before interest & tax	₹ Lacs	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>197</i>	<i>139</i>	<i>15</i>
7	Return on capital employed	%	***	***	***	***
	<i>Trend</i>	<i>Indexed</i>	<i>100</i>	<i>150</i>	<i>106</i>	<i>11</i>

60. It is seen that the domestic industry was earning good profits till the preceding year. However, the profits of the domestic industry have declined sharply in the period of investigation. Resultantly, the cash profits and the return on investment have also been impacted.

e. Employment, wages and productivity

61. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity was examined.

S.No.	Particulars	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	No of employees	Nos	695	757	783	775
2	Salary & wages	₹ Lacs-Trend	100	121	127	130
3	Productivity per day	MT/Day	779	810	787	770
4	Productivity per employee	MT/Nos	392	374	352	348

62. It is seen that employment levels of domestic industry have fluctuated over the injury period and wages paid have increased over the injury period. The productivity per employee and per day increased in 2017-18 but declined thereafter with a decline in production.

f. Growth

63. Examination of growth parameters of the domestic industry during the injury period is shown below –

S.No.	Particulars	UOM	2016-17	2017-18	2018-19	POI
1	Production	Y/Y	-	4%	-3%	-2%
2	Capacity Utilization	Y/Y	-	4%	-3%	-2%
3	Domestic Sales	Y/Y	-	6%	1%	-4%
4	Profit/(Loss) per unit	Y/Y	-	103%	-32%	-97%
5	Inventory	Y/Y	-	-40%	-4%	44%
6	Market Share	Y/Y	-	-4%	-2%	-9%
7	Profit/(Loss) in Rs Lakhs	Y/Y	-	115%	-31%	-98%
8	Cash Profit in Rs Lakhs	Y/Y	-	98%	-28%	-84%
9	PBIT in Rs Lakhs	Y/Y	-	97%	-29%	-89%
10	ROI %	Y/Y	-	50%	-29%	-90%

64. It is seen that most of the performance parameters of the domestic industry show a negative growth in the period of investigation.

g. Magnitude of dumping

65. It is seen that the dumping margin in the imports from the subject countries is not only positive but also significant

h. Ability to raise fresh investment

66. Considering performance of the domestic industry in the period of investigation, it is seen that the ability of the company to raise fresh investments is likely to be impaired. If the domestic industry is earning profits at these levels.

i. Factors affecting domestic prices

67. It is seen that the selling price of the domestic industry are affected as it is unable to earn adequate returns. Imports from subject countries are not a factor affecting the domestic prices.

j. Observations on injury

68. Considering various parameters relating to material injury, it is seen overall performance of the domestic industry is poor. There is a sharp decline in the volume of dumped imports from the subject countries, in absolute terms and in relation to production and consumption in India. There is presence of suppressing effect on the domestic selling prices but it cannot be attributed to dumped imports. Performance of the domestic industry has deteriorated in respect of capacity utilisation, production, sales, market share, profits, cash profits and return on investment. The domestic industry has suffered injury and the situation of the domestic industry is fragile.

H CAUSAL LINK

69. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the AD Rules could have contributed or are likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry

a. Volume and price of imports from third country

70. It is seen that the volume of imports from China, Indonesia, Korea RP, Thailand and Taiwan are above di-minimis limits. Applicant claimed that imports from these countries are at dumped prices. The Authority has initiated investigation in respect of imports from China, Indonesia, Korea RP and Thailand vide notification no. 6/16/2020 dated 21st May 2020. Further, the Authority has recommended bilateral safeguard measures by removal of concession over custom duty payable on imports of Korea RP. Imports from Taiwan are above the non-injurious price of the domestic industry and therefore cannot be a cause of injury to the domestic industry.

b. Contraction in Demand and / or Change in Pattern of Consumption

71. The demand of the subject goods has increased as compared to base year. The pattern of consumption with regard to product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have, therefore, contributed to the injury to the domestic industry.

c. Development of Technology

72. The Authority notes that technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a possible factor of injury.

d. Trade restrictive practices

73. The Authority notes that there is no trade restrictive practice, which could have caused injury to the domestic industry.

e. Export performance

74. The applicant has contended that it has been forced to undertake exports in the period of investigation due to dumped imports in the domestic market. The applicant contended that the exports made by the domestic industry – both in terms of volume and price – should be considered a result of dumping in the country. It is seen that export sales of the domestic industry have increased sharply in the period of investigation and profitability in exports was far less as compared to domestic sales. The domestic industry has suffered financial losses in exports. While the Authority has relied on segregated data for domestic and export operations, to the extent the same could be, for the purpose of injury analysis of the domestic industry, the fact that the domestic industry was forced to export at significantly low and unremunerated prices is a reflection of adverse impact of imports on the domestic industry. Further, since export volumes and profits have been segregated, possible decline in export performance is not cause of the injury considered hereinabove.

f. Performance of other products

75. The Authority has considered the data relating to the performance of the subject goods only. Therefore, performance of other products produced and sold by the applicants are not a possible cause of the injury to the domestic industry.

I MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

76. The injury margin has been evaluated by comparing the non-injurious price with the landed price of the subject imports.

S.No.	Particulars	Non-injurious price (NIP)	Landed price	Injury margin	Injury margin	Range
		RS/MT	RS/MT	RS/MT	%	%
1	Japan	***	60,985	***	***	0-10%
2	Russia	***	65,815	***	***	0-10%

77. It is seen that the injury margin is positive in respect of dumped imports from both the subject countries.

J LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY

78. In a review investigation, the Authority has to determine whether the subject goods are continuing to enter or likely to enter the Indian market at dumped prices and whether injury to the domestic industry is likely to continue or recur due to these dumped imports if the duty is removed.

J.1. Submissions by Domestic industry

79. The submissions of the domestic industry with regard to likelihood of injury are reproduced herein below:
- Producers in both the subject countries are currently operating with idle capacities.
 - Demand as a percentage of production in both the subject countries is considerably low which shows that the significant production is accounted for exports.
 - Significant exports to third countries are at dumped and injurious prices.
 - The volume of imports which are at dumped and injurious prices constitutes significant share of Indian demand.
 - There are significant volumes of exports which can be diverted to India because of attractive Indian market, in case of revocation of duties.
 - Future projections for capacity and production in the next three years show that the capacities in both the countries will remain idle.
 - India has been a primary market for Russian producers in past as it has held around 34% share in exports.
 - Imports from Japan enjoy concessional duty and users will always be incentivised to import from Japan.
 - If domestic industry is forced to match its prices with price of imports from subject countries, it will bleed in losses and a negative return.
 - Price undercutting without anti-dumping duty is positive in case of both the subject countries which shows likelihood of injury.
 - Landed price of imports from both Japan and Russia is reasonably below the landed price of imports from China, Indonesia, Korea RP and Thailand which are causing an injury to the domestic industry.

- xii. Volume of imports in post period of investigation from Japan are at a highest level considering the present injury period.
- xiii. Imports from Russia have recorded a significant jump in the post period of investigation.
- xiv. Increasing imports in the post period of investigation is also a likelihood of injury to the domestic industry.
- xv. Imports from both the countries are above di-minimis limits in post period of investigation (even though de-minimis provision does not apply in case of a review). Mere increase in prices without examining the movement in prices of raw material is misleading.
- xvi. As regards the submission that subject imports were never a major source of imports, before duties were recommended, it is submitted that imports from both the subject countries were above di-minimis limits leading to present duties.
- xvii. Average export price to a large number of third countries in fact has no meaning as prices are decided for individual sale transactions and weighted average would only present distorted picture. As regards the submission that the domestic industry has increased its prices in the post period of investigation, it is submitted that no verifiable evidence has been provided.

J.2 Submissions by other interested parties

80. The submissions of other interested parties with regard to likelihood of injury are reproduced herein below:
- i. Applicants have admitted that domestic industry did not suffer any continued injury on account of import of subject goods from subject countries.
 - ii. Share of subject countries imports is negligible and duty needs to be terminated.
 - iii. Prices from subject countries have increased from Rs 49.37/Kg to Rs 60.76/- in the period of investigation.
 - iv. Reduction in volume and increase in price shows that exporters are not under any pressure to export at lower prices.
 - v. Positive price undercutting in the present matter could be on account of very high price charged by the domestic industry.
 - vi. PAN has a balanced demand supply situation in the world and the subject countries are not a major source of supply.
 - vii. Subject countries were not major source of imports prior to imposition of anti-dumping duty. Even if import goes back to pre-duty levels, it would be very negligible.
 - viii. Injury margin and dumping margin on third countries exports shows a misleading situation.
 - ix. Performance of domestic industry in post period of investigation is very robust and published results of IGPL and TCL shows significant increase in profits.
 - x. Selling price of product under consideration in domestic market has increased by 25 to 30% without any proportionate increase in raw material prices.
 - xi. Claims of likelihood are unsubstantiated

J.3 Examination by Authority

81. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A(5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the Anti-dumping rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties. The Authority notes as under.
82. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of subject goods from Japan and Russia. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of injury to the domestic industry. Further,

the Authority has also examined other relevant factors which could have a bearing on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry

83. The Authority notes that the applicants have relied on the Tecnon Orbi Chem Report for information with respect to capacities, production and demand in the subject countries. None of the producers from the subject countries have participated in the investigation and other interested party have not brought forward any justifiable information/evidence disputing the claims made by the domestic industry. While Govt. of Russia has participated in the present investigations, no verifiable information has been provided by them with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

J.3.1 Capacities in subject countries

84. Information with respect to unutilised capacities is given below.

S.No.	Particulars	2016	2017	2020	2023
1	Capacity (in kT)	457	457	457	457
a	Russia	282	282	282	282
b	Japan	175	175	175	175
2	Production (in kT)	274	282	299	309
a	Russia	124	131	139	144
b	Japan	150	151	160	165
3	Utilization in %	60%	62%	65%	68%
a	Russia	44%	46%	49%	51%
b	Japan	86%	86%	92%	94%
4	Idle capacities	183	175	158	149
a	Russia	158	151	143	138
b	Japan	25	24	15	11

85. It is seen that significant capacities of the producers in subject countries are unutilised in case of Russia, while the capacities are significantly utilised in case of Japan. Further, projections for next few years show that the capacities in Russia will remain significantly unutilised, whereas the capacities in Japan would be increasingly utilised.

J.3.2 Export orientation

86. Information with regard to the surplus production over demand in the subject countries is as under:

S.No.	Particulars	2016	2017	2020	2023
1	Total Production (in kT)	274	282	299	309
A	Russia (in kT)	124	131	139	144
B	Japan (in kT)	150	151	160	165
2	Total Consumption (in kT)	193	195	201	207
A	Russia (in kT)	88	89	95	99
b	Japan (in kT)	105	105	106	109
3	Consumption as a % of production	70%	69%	67%	67%
a	Russia	71%	68%	68%	69%
b	Japan	70%	70%	66%	66%
4	Consumption as a % of capacity	42%	43%	44%	45%

a	Russia	31%	32%	34%	35%
b	Japan	60%	60%	61%	62%

87. It is seen that the current demand in the subject countries is less than 70% of the production. Further, consumption as a percentage of capacity is low in Russia, while the same is high in case of Japan.

J.3.3 Third country dumping and injury

88. The table below shows volume of exports by these exporters to third countries at dumped, attractive and injurious prices.

SN	Particulars	Exports from Russia to third country	Exports from Japan to third country
1	Volumes below NIP	29,259	36,662
2	Volumes above NIP	26,953	8,185
3	Volumes below normal value	47,638	44,484
4	Volumes above normal value	8,573	363
5	Volumes below Indian prices	37,244	42,111
6	Volumes above Indian prices	18,968	2,736
7	Demand in India	4,02,500	4,02,500
8	Exports in relation to demand		
a	Volume below normal value (dumped) in %	11.84%	11.05%
b	Volume below NIP (injury) in %	7.27%	9.11%
c	Volume below Indian price in %	9.25%	10.46%

89. Analysis of exports from Japan and Russia to third countries out of total exports shows as follows: -
- Exports at price below normal value constitute 11.84% (Russia) and 11.05% (Japan) of Indian consumption.
 - Exports at price below non-injurious price of the domestic industry were 7.27% (Russia) and 9.11% (Japan) of Indian demand.
 - Exports at price below Indian price were 9.25% (Russia) and 10.46% (Japan) of Indian demand.

J.3.4 Post-POI Analysis

90. Authority has also conducted an analysis for the post period of investigation (April 2020 to August 2020) for the purposes of determining likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury. It is seen that the volume of imports from both the subject countries have increased sharply in the period post the period of investigation which shows that there is a likelihood of further increase in imports, if duty is allowed to expire. Further, the Authority notes that the performance in the post POI in any case is not likely to be representative due to country wide lockdown in India due to Covid pandemic.

S.No.	Particulars	2016-17	2017-18	2018-19	POI	Post POI (A)
1	Subject imports	5,866	10,037	11,171	5,732	17,841
2	Japan	350	-	-	300	3,888
3	Russia	5,516	10,037	11,171	5,432	13,953

91. It is seen that the volume of imports from both the subject countries have increased sharply in the period post the period of investigation which shows that there is a likelihood of further increase in imports.

J.3.5 Likely performance of the domestic industry if duties are not extended

92. The applicant has claimed that if it was forced to match its selling prices with the imports, it would have suffered significant losses. The Authority has compared the landed price of imports from the subject countries and cost of domestic industry. It is seen that the landed price of imports from the subject countries is below the cost of domestic industry. If there is an increase in imports from the subject countries, domestic industry would be forced to match its prices with the imports which would result in losses.

K POST DISCLOSURE SUBMISSIONS

93. The Authority notes that most of the submissions made by the interested parties in response to the disclosure statement are repetitive in nature and the interested parties have largely reiterated their earlier submissions, which have already been examined and addressed by the Authority.

Following are new submissions made by the domestic industry and other interested parties on the disclosure statement issued by the Authority.

K.1 Submissions by domestic industry

94. Following submissions have been made by the domestic industry:
- i. Complete disclosure of non-injurious price including Format B, D, expenses allowed/disallowed, optimum capacity utilisation used and capital employed details is requested. Even though the non-injurious price has been determined based on the data of the domestic industry, the calculations have not been provided and domestic industry is unable to comment on non-injurious price determined.
 - ii. Authority has ignored freight in calculating the injury margin.
 - iii. The same quantum of duty may be extended as current duties are serving purpose of protecting the domestic industry against the continued dumped imports.
 - iv. Rosplast OOO LLC, Russia participated in the original investigation but has not responded to the current investigation. This may be noted while recommending duty.
 - v. Imports from subject countries in September 2020 shows a similar increase.
 - vi. Dumping from subject countries has continued even when duties are in place which shows that producers are likely to continue or even intensify dumping in the absence of duties.
 - vii. Positive price undercutting further substantiates that it is the anti-dumping duty in force which has prevented imports from causing injury to the domestic industry.
 - viii. Positive price underselling or injury margin from both the subject countries shows that the imports are injurious to the domestic industry.
 - ix. Pakistani National Tariff Commission has initiated an antidumping investigation on imports of subject goods from Russia. This highlights export orientation and third country dumping by Russian producers. If duties are imposed by Pakistan, it will lead to closure of another market for them.
 - x. Looking at the ratio of price of finished goods to raw material prices, it is lower for subject countries in comparison to average world level. Producers in Japan and Russia are keeping their prices lower than the market prices in order to maintain their export market.
 - xi. Users and association have made mere statements and have not been able to quantify the adverse effect of duties. No information has been provided to establish adverse effect of duty on the consumers.
 - xii. Consumption of the subject goods has significantly improved in last one decade. This clearly shows that the duties have had no adverse impact on the users.

- xiii. Commercial production in new plants of Thirumalai Chemicals and IG Petrochemicals is expected to begin soon. Capacity after expansions will be much more than the projected demand in India.
- xiv. KLJ Plasticizers Limited is setting up new plant of 2 lacs MT. Capacities in India are expected to be in the range of 7 lacs MT which will be more than the likely demand in India.
- xv. With no demand-supply gap and no reliance on imports, Indian Phthalic Anhydride industry will become a totally an AtmaNirbhar Industry.
- xvi. In past investigations, it has been repeatedly found that imposition of trade measures will not be against the public interest.
- xvii. DG Safeguards found safeguard duty (which is against fairly priced imports) in public interests. In the present case, the issue is unfair dumping of the product.
- xviii. Ministry of Finance has recently imposed bilateral safeguard measures on the imports of Phthalic Anhydride from Korea RP after recommendation from the Authority. The Authority had already found that the imposition of measures was not against public interest.
- xix. Anti-dumping duty is a redressal of unfair price discrimination by the producers in other countries, which is injurious to the industry in India. It is not a protection to the industry, but rather a means of addressing unfair pricing.
- xx. There are three producers in India and imports happening from multiple sources and there is going to be another fresh entrant in the market. There is enough inter-se competition and the domestic industry will have to keep a check on its prices.
- xxi. Public interest does not limit itself to the consumer industry alone and is in fact a much wider term which covers in its ambit the domestic industry as well.
- xxii. M/s Thirumalai Chemicals Limited and M/s IG Petrochemicals Limited have already made an investment of around Rs 135 crs and Rs 345 crs for new plants. M/s Thirumalai Chemicals Limited is further investing around Rs 450 cr. for a new green field project of subject goods. With such significant investments being undertaken, it is necessary to impose suitable measures to prevent the unfair trade practices followed by exporters from the subject countries.
- xxiii. Government of India has been promoting the Make in India campaign and the ideology of Atma Nirbhar Bharat, but the Indian Phthalic Anhydride industry user industry are heavily resorting to imports.
- xxiv. It will be seen that ratio of exports to imports has fallen over the years to such an extent that whereas exports were earlier far higher than imports, imports are now far higher than exports. The ratio of exports to Imports has fallen from about 3.93 in 2001-02 to 0.17 in the year 2019-20

K.2 Submissions by other interested parties

95. Following submissions have been made by other interested parties on the disclosure statement:

- i. The Authority has not disclosed basis of normal value in the disclosure statement, which is in violation of Rule 16.
- ii. Position taken on injury in present case is contrary to finding in safeguard matter against Korea RP.
- iii. Observation that price underselling is positive from both subject countries has no meaning in present matter as subject imports did not cause any injury.
- iv. Injury margin is not any parameter of injury as has been ruled by the Hon'ble Gujarat HC.
- v. Disclosure statement undermines the fact that imports during entire injury period from subject countries were very negligible in comparison to Indian demand and continuation of duties on such imports has no justification.

- vi. Submission of association on performance of the domestic industry in post period of investigation has not been addressed by the Authority in the disclosure statement.
- vii. If the Authority conducts post POI examination, it may conduct examination for both dumping and injury related parameters and should not restrict examination only to volume of imports which as a standalone parameter is indicative of nothing.
- viii. Information on likelihood relied upon in disclosure statement is based on uncorroborated evidence and the Authority has not verified the veracity of such data. Summary data cannot satisfy the requirements of disclosure of essential facts.
- ix. If subject countries were source of unutilized capacities and third country dumping as is projected in disclosure statement, share of imports from such countries would have been much higher.
- x. Basis of third country prices is not provided for examination of third country exports from subject countries which are above and below NIP and Normal Value.
- xi. KLJ Plasticizers Limited has plans for 100KT plant and we are unaware about the evidence of capacity expansion for 200 KT. The capacities may become operational in the next 3 plus years and it is unfair for the Authority to subject essential imports from subject countries to duty till all such capacities become operational.

K.3 Examination by Authority

- 96. The Authority notes that most of the submissions by the domestic industry and other interested parties are repetitive in nature. These submissions have already been examined at appropriate places in this finding. Further, the Authority has examined additional/new relevant submissions of the interested parties as under
- 97. The scope of domestic industry is different in the safeguard investigations concerning imports from Korea and the present sunset review investigations. M/s SI Group India Private Limited was not within the scope of domestic industry in the bilateral safeguard investigation. Therefore, the economic parameters of the domestic industry in both the investigations cannot be directly compared.
- 98. On the submission of both the interested parties on consideration of the post period of investigation data, the Authority notes that period of post period of investigation will include the period of COVID-19 pandemic and associated lock-down and therefore may not conclusively establish the need for either withdrawal or extension of duties. The performance of the domestic industry and the imports into India both were affected due to countrywide lockdown in India due to Covid pandemic.
- 99. In regard to the submission that the imports from subject countries were never a major source of imports, the Authority notes that the imports from subject countries in the original investigation were above the de-minimis limit prescribed under the Rules.
- 100. With regard to the issue raised in respect of the source of third country export data and the information on likelihood, it is noted that in the absence of participation from the foreign producers from the subject countries and non-provision of any such verifiable data from any other interested party, the Authority has relied on the facts available and has considered the customs data publicly available and provided by the Applicants.
- 101. On the submission of capacity expansion, it is noted that domestic industry had provided a document showing capacity expansion of 200 KT. The association has contended that the capacity expansion will be of 100 KT and will take 3 years to complete. It is noted that two existing producers have already expanded their capacity and the commercial production in respect of expanded capacity is going to start soon. Even if the planned capacity expansion of KLJ Plasticisers is considered as 100 KT, it is seen that the domestic producers will be able to cater to complete demand of the product in India. In any case, the users are free to import the subject goods at fair price.
- 102. On the submission made by the domestic industry concerning computation of non-injurious price and disclosure thereof, it is noted that the non-injurious price has been determined in accordance with Annexure III of the Rules. The NIP has been disclosed to the domestic industry, consistent with the practice followed in this regard.

103. On the submission with regard to examination of parameters for injury, it is noted that the Authority has examined all the parameters of injury as per its consistent practice.
104. As regards non-disclosure of normal value, it is clarified that the foreign producers have not cooperated with the authority in the present investigation and therefore the authority was constrained to determine normal value based on facts available. Further, the normal value determined includes confidential information of the applicant domestic industry. Disclosure of normal value would have therefore led to disclosure of confidential information of the applicant domestic industry.
105. It is seen that there were three import transactions of imports from Japan over the entire injury period. The import of product under consideration from Japan over the injury period was meagre 650 MT in import of 5,08,797 MT and Indian demand of 14,96,364 MT over the injury period. Consumption of product under consideration in relation to capacity is quite high in case of Japan thus showing significant domestic consumption. It is noted that the existing capacity utilisation of Japanese producer is also significantly high. Whereas Japanese producer's average capacity utilisation over the injury period was 86-92%, the average capacity utilisation of Russian producers over the period was 60-65%. It is thus concluded that Japanese producers are substantially utilising their capacities and are having significant domestic consumption. On the contrary, Russian producers' existing capacity utilisation is quite low and the consumption as percentage of capacity is also very low in Russia unlike Japan. The authority therefore concludes that while there is no likelihood of significant increase in imports from Japan, there is likelihood of significant increase in imports from Russia in the event of cessation of ADD on account of huge unutilised capacity there.

L INDIAN INDUSTRY'S INTEREST

106. The Authority notes that the purpose of ADD, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country/territory in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
107. It is noted that fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the ADD is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the Domestic Industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

M CONCLUSION

108. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the Domestic Industry, the Authority concludes that:
 - a. There is continued dumping of the subject goods from the subject countries.
 - b. The domestic industry has suffered injury.
 - c. Factors such as volume of imports over injury period, domestic consumption in Japan, the capacity utilisation of the Japanese producers over the period, show no likelihood of injury to the domestic industry in case the ADD in force on imports from Japan is allowed to cease.
 - d. Factors such as positive price undercutting, excess production over demand, idle production capacities in Russia, price attractiveness of Indian market, third country dumping show likelihood of dumping and injury to the domestic industry in case the ADD in force on imports from Russia is allowed to cease.
 - e. Factors such as significant capacity expansions in the country which will remove demand-supply gap, inter-se competition among Indian producers show that there may not be adverse effect of duties on the consumers or downstream industry.

N RECOMMENDATIONS

109. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link.
110. Having concluded that there is likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry if the existing anti-dumping duty against imports from Russia is allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of anti-dumping duty is required on the imports of the product under consideration from Russia. However, cessation of anti-dumping duty on imports of the product under consideration from Japan is not likely to lead to injury to the domestic industry.
111. Under these circumstances, the Authority considers it appropriate to recommend continuation of existing quantum of anti-dumping duty on the imports of subject goods from Russia. The Authority, thus, considers it necessary to recommend continuation of definitive ADD equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table below for a period of five (5) years on all imports of the subject goods mentioned in column 3 of the duty table from Russia.

DUTY TABLE

S.No.	Heading/ Subheading	Description of subject goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	29173500	Phthalic Anhydride	Russia	Any country including Russia	Any	159.43	MT	US\$
2	29173500	Phthalic Anhydride	Any country other than Russia	Russia	Any	159.43	MT	US\$

O FURTHER PROCEDURE

112. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority